घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 133- सोमवार 16- मार्च 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल व पुडुचेरी में बजा चुनाव का बिगुल....

तमिलनाडु में 23 अप्रैल, असम-केरल-पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग,नतीजे 4 मई को

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। चुनाव आयोग ने रविवार को देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसके तहत पुडुचेरी,केरल और असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वहीं, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा,जिसमें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि संबंधित पांच राज्यों में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

चुनाव के लिए 824 विधानसभा सीटों पर करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव कर्मी तैनात किए जाएंगे। आयोग के मुताबिक,पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा,जबकि तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई तक है। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई और केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा का कार्यकाल 15 जून तक है। विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 824 सीटों में से असम में 126, केरल में 140, पुडुचेरी में 30, तमिलनाडु में 234 और पश्चिम बंगाल में 294 सीटें शामिल हैं। इन राज्यों में कई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

चुनाव आयोग का ऐलान- मतदान केंद्रों के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

चुनाव आयुक्त ने कहा- मैं युवाओं से वोट डालने की अपील करता हूं

चुनाव आयुक्त ने कहा- 'मैं युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। वे वोट जरूर करें। आपका वोट आपकी वॉइस है जो भविष्य का निर्माण करेगा। भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व है।

किस राज्य में कितने मतदाता

राज्य	पुरुष	महिला	कुल मतदाता
असम	1.25 करोड़	1.25 करोड़	2.50 करोड़
केरल	1.31 करोड़	1.38 करोड़	2.70 करोड़
पुडुचेरी	4.43 लाख	5 लाख	9.44 लाख
तमिलनाडु	2.77 करोड़	2.89 करोड़	5.67 करोड़
पश्चिम बंगाल	3.28 करोड़	3.16 करोड़	6.44 करोड़

पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा

पश्चिम बंगाल	तमिलनाडु	असम
दो चरण	एक चरण	एक चरण
23, 29 अप्रैल	23 अप्रैल	09 अप्रैल
केरल		**पुदुचेरी**
एक चरण	04 मई को नतीजे	एक चरण
09 अप्रैल		09 अप्रैल

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा... हमने 12 महीने में कई प्रयोग किए...

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया-' पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था एसआईआर , जिसमें यह निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। दूसरा- मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाएगा। वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। एक पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोटर्स न हों। सभी जानकारी चुनाव से जुड़ी जिनमें एपिक कार्ड, प्रत्याशियों के हलफनामे एक एप पर उपलब्ध हैं।

बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता का बड़ा दांव

पश्चिम बंगाल में पुजारियों-मुअज्जिनों का मानदेय 500 बढ़ा,अब हर महीने 2000 मिलेंगे

कोलकाता,15 मार्च 2026। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। राजनीतिक दल अपने-अपने चुनावी रण की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में जारी रैलियों और रणनीति बैठकों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उन्होंने राज्य के पुजारी और मुअज्जिनों की मासिक मानदेय राशि 500 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। अपने पोस्ट में सीएम ने कहा कि ये लोग हमारी समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें यह सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही, जिन्होंने नए आवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए थे, उन्हें भी मंजूरी दे दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार हर समुदाय और परंपरा का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक को पूरा सहयोग और मान्यता मिले।

कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर भी बड़ा ऐलान : इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर भी बड़ा एलान किया। एक अलग पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के शैक्षिक संस्थानों के लाखों शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ, तथा पंचायत,नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए अपना वादा पूरा कर दिया है।

एनएचएआई ने वार्षिक फास्टैग के दाम 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपये किये,1 अप्रैल से लागू

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए फास्टैग वार्षिक पास के शुल्क को 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दिया है। नए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। देश में निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग वार्षिक पास को तेजी से अपनाया जा रहा है और वर्तमान में इसके 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं। वार्षिक पास को 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। प्राधिकरण के अनुसार इसे देशभर के राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। संशोधित शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय द्रुतमार्गों के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर लागू होगा। यह सुविधा केवल वैध फास्टैग वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपलब्ध है।

राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज के नेता कांशीराम की जयंती पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आधिकारिक पत्र लिखकर पत्र लिखकर कहा कि कांशीराम ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से बहुजनों और गरीबों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और भागीदारी का अधिकार देता है। कांशीराम ने समाज के सबसे निचले तबके तक इन अधिकारों को सार्थक बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इससे भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई और राजनीतिक व्यवस्था अधिक प्रतिनिधिक तथा न्यायपूर्ण बनी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम ने लोगों को यह याद दिलाया कि उनका वोट, उनकी आवाज और उनका प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है और यह देश सभी का समान रूप से है। उनके प्रयासों के कारण उन लोगों ने राजनीति को न्याय और समानता हासिल करने का माध्यम माना, जिन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन में आने के बारे में नहीं सोचा था। राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने से राष्ट्र के प्रति उनके विशाल योगदान को मान्यता मिलेगी और उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान होगा, जो उन्हें सशक्तिकरण और आशा के प्रतीक के रूप में देखते हैं।

जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही : योगी आदित्यनाथ

चित्तौड़गढ़,15 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों ने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। योगी आदित्यनाथ रविवार को जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। यह जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 'मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का,वीरों का,धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का?' ये महाकवि दिनकर की पंक्तियां हैं।

नेताजी बोस होते तो पापी पाकिस्तान नहीं होता

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा,जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण न करता हो? उन्होंने भी तो आह्वान किया था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' यह नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था,पूरे भारत की आजादी के लिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका यह आह्वान भारत की अस्मिता के लिए था,भारत की आजादी के लिए था।

भाजपा की सरकार में एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा : शाह

गुवाहाटी,15 मार्च 2026। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो), असम प्रदेश के सौजन्य से गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 'युवा शक्ति समारोह' में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए राज्य में घुसपैठियों का संरक्षण करने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य के सामूहिक विकास के लिए भाजपा को वोट देने का आह्वान किया। रविवार को राज्य के 1.5 लाख से अधिक युवाओं को गृह मंत्री ने संबोधित करते हुए उपरोक्त आह्वान किया। इस कार्यक्रम में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और दरंग-उदालगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद दिलीप सैकिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेरिटा और प्रदेश भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद एवं विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। भाजयुमो के इस कार्यक्रम के जरिए आज राज्य के प्रत्येक जिले के युवा मतदाताओं ने भाजपा की चुनावी रणभेरी बजाई। असम के विकास और उत्थान की यात्रा में युवा शक्ति के संकल्प को दृढ़ करने के लिए यह युवा शक्ति समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की युवा शक्ति के इस महासमागम ने राज्य में भाजपा के जनसमर्थन की मजबूत तस्वीर पेश की है। उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने उन्हें फोन करके युवाओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह का विशाल युवा सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकी है। उन्होंने असम के युवाओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।

अमित शाह ने कहा कि हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में असम में विकास की प्रक्रिया जारी है। शाह ने दावा किया कि असम सरकार ने किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना लगभग 1 लाख 65 हजार नौकरियां प्रदान की हैं, जो राज्य के इतिहास में एक उल्लेखनीय कदम है। समारोह में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस दल की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिनों में चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी 94 रुपये थी। भाजपा के दिनों में हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने इसे 280 रुपये तक बढ़ा दिया। कांग्रेस अपने लोगों के बारे में सोचती है, भाजपा असम के बारे में सोचती है। गृह मंत्री के अनुसार कांग्रेस के शासनकाल में असम की भाषा और संस्कृति (जाति, माटी, भेटी) का सम्मान नहीं किया जाता था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक वीर लचित बरफूकन का गौरव विश्व के सामने उज्जवल रूप से प्रस्तुत किया गया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार के समय लगभग 10,800 हथियारबंद लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में शांति और अनुशासन मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठियों के कब्जे वाली बड़ी मात्रा में भूमि को मुक्त कराया गया है और आने वाले समय में यह अभियान जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की अगली सरकार में एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा।

तेलंगाना में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का खुलासा

टीडीपी सांसद सहित 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा

हैदराबाद,15 मार्च 2026। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद क्षेत्र में स्थित एक फार्महाउस में कथित तौर पर आयोजित ड्रग्स पार्टी का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बड़ा विवाद बन गया है। इस पार्टी में उद्योगपतियों,रियल एस्टेट कारोबारियों और राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी सामने आने के बाद मामला और भी सनसनीखेज हो गया है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार,उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मोइनाबाद के अजीजनगर स्थित एक फार्महाउस में ड्रग्स के साथ पार्टी चल रही है। सूचना मिलते ही 'ड्रग लॉ एनफोर्समेंट के लिए एलीट एक्शन ग्रुप' (ईगल) की पांच सदस्यीय टीम ने शनिवार रात करीब 9:30 बजे फार्महाउस पर छापा मारा। हालांकि, छापेमारी के दौरान पुलिस को फार्महाउस के अंदर प्रवेश करने में शुरुआती विरोध का सामना करना पड़ा। बताया गया कि गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और फार्महाउस के मालिक तथा पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस टीम को तुरंत अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस टीम (एसओटी) को मौके पर बुलाया,जिसकी मदद से टीम ने फार्महाउस के अंदर प्रवेश किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फार्महाउस से करीब दो ग्राम कोकीन बरामद की। जांच में यह भी सामने आया कि पार्टी में कुल 11 लोग मौजूद थे,जिनमें से छह लोगों का ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। ईगल टीम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गिरिधर ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन छह लोगों का ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया है,उनमें पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी,एलुरु के टीडीपी सांसद पुट्टा महेश कुमार यादव,रितेश रेड्डी,नमित,कौशिक रवि और अर्जुन रेड्डी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सांसद पुट्टा महेश कुमार यादव का शनिवार रात को किया गया रैपिड ड्रग टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन बाद में किए गए ब्लड टेस्ट में उनका परिणाम पॉजिटिव पाया गया। पुलिस का यह भी आरोप है कि जांच के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी,जिसकी भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, पार्टी के दौरान राजस्थान के एक पूर्व विधायक ने कथित तौर पर रोहित रेड्डी के भाई की बंदूक से हवा में दो राउंड फायरिंग की। इसी दौरान पुलिस को गोलियों की आवाज सुनाई दी।

बेंगलुरु रिसॉर्ट में ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश,दो संदिग्ध पकड़े गए

बेंगलुरु,15 मार्च 2026। राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कथित 'ऑपरेशन कमल' की आशंका के बीच ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश का मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास सामने आया है। इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, ओडिशा के कांग्रेस विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु के पास बिदादी स्थित वंडरला रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए थे। इसी दौरान शनिवार की रात चार लोग रिसॉर्ट में कमरा बुक कर वहां ठहरे थे। रविवार सुबह उनमें से एक व्यक्ति ने एक ओडिशा कांग्रेस विधायक से बातचीत की और उनके साथ फोटो लेने की कोशिश की। इसे देखकर वहां मौजूद स्थानीय कांग्रेस नेताओं को संदेह हुआ। संदेह होने पर जब उनसे पूछताछ की गई, तो दो लोग मौके से भाग निकले, जबकि दो लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान बिरेंद्र प्रसाद और अजीत कुमार साहू के रूप में हुई है। दोनों को बिदादी पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा से कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलका ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की।

बंगाल में तृणमूल से तंग आ चुके हैं लोग,इस बार बनेगी भाजपा की सरकार : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा सत्ता में आएगी, क्योंकि लोग तृणमूल से तंग आ चुके हैं। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के तारीखों की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम हर चीज के लिए हमेशा तैयार हैं। हम देश के लिए कुछ भी करेंगे और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। टीबी मुक्त भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस और सांसदों के बीच हुए क्रिकेट मैच के बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा कि सांसद कितने अच्छे तरीके से मैच खेल रहे हैं,इसको देखकर मैं बहुत उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया चलाया,फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, अब टीवी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में देश के लोग जुट गए हैं। इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है।

आरएसएस ने चुनावों के दौरान जाति-आधारित मतदाता विश्लेषण को समाप्त करने की मांग की

चंडीगढ़,15 मार्च 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (अखिल भारतीय प्रतिनिधियों की सभा) की तीन-दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और चुनावों के दौरान मतदाताओं के जनसांख्यिकीय आंकड़ों का जाति-आधारित विश्लेषण करने की प्रथा को रोकने का आह्वान किया गया। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में मीडिया वालों से कहा कि संघ सामाजिक सद्भाव का समर्थन करता है और समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिशों का विरोध करता है। होसबले ने मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के बीच केंद्र सरकार की कूटनीतिक कोशिशों की भी तारीफ की, और कहा कि संघ 'वैश्विक शांति और विकास का समर्थक है'। उन्होंने कहा कि आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने इस संगठन की स्थापना किसी खास समुदाय,धार्मिक संप्रदाय या पूजा-पद्धति का विरोध करने के इरादे से नहीं की थी। उन्होंने कहा, 'पूजा-पद्धति और रीति-रिवाजों में अंतर से कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। 'यह कहते हुए कि संगठन में सभी का स्वागत है, होसबले ने कहा,'हम समाज की भलाई के लिए रचनात्मक काम में लगे किसी भी व्यक्ति को संघ का स्वयंसेवक (वॉलंटियर) मानते हैं।

संपादकीय

हर घर जल की दिशा में नया चरण और डिजिटल निगरानी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह जल जीवन मिशन (जेजेएम) के पुनर्गठन और इसे 2028 तक आगे बढ़ाने की योजना को मंजूरी प्रदान की। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी की पहुंच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। नल-जल कवरेज 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (कुल का लगभग 17 फीसदी) से बढ़कर आज लगभग 15.8 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया है, जो राज्यों द्वारा पहचाने गए 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 81 फीसदी से अधिक को कवर करता है। ऐसे में अगला चरण जिसे जेजेएम 2.0 कहा जा रहा है, एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपये का विस्तारित परिव्यय होगा। इसमें केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी, जबकि 2019-20 में 2.08 लाख करोड़ रुपये की ही स्वीकृति दी गई थी। बात सिर्फ धन की नहीं है, नए सिरे से तैयार डिजाइन इसे नागरिक-केंद्रित उपयोगिता-आधारित सेवा वितरण कार्यक्रम बनाता है। बदलावों में एक प्रस्तावित समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा 'सुजलाम भारत' शामिल है, जो प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सेवा-क्षेत्र पहचान दस्तावेज या आईडी प्रदान करेगा और पूरी पेयजल आपूर्ति श्रृंखला को स्रोत से लेकर नल तक निर्धारित करेगा। इस एकीकृत निगरानी प्रणाली से पारदर्शिता और सेवा निगरानी में सुधार की उम्मीद है। ग्राम पंचायतों और गांव की जल एवं स्वच्छता समितियों की मजबूत भूमिकाओं के माध्यम से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी ताकि 'हर घर जल' की घोषणा के लिए पर्याप्त गांव-स्तरीय संचालन और रखरखाव तंत्र स्थापित हो सके। वहीं 'जल उत्सव' जैसी पहलें समुदाय की भागीदारी को गहरा करने, गांव की जल प्रणालियों की समीक्षा करने और पेयजल के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को सुदृढ़ करने का प्रयास करती हैं।

मिशन के पहले चरण ने नल कनेक्शनों के तेजी से विस्तार को प्राथमिकता दी, लेकिन टिकाऊ सेवा के मामले में असमानता बनी हुई है। स्वतंत्र आकलन और क्षेत्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि कई गांव अब भी अनियमित जल आपूर्ति,सीमित उपचार क्षमता या खराब रखरखाव वाली अधोसंरचना का सामना कर रहे हैं। संचालन और रखरखाव, जो अक्सर ग्रामीण अधोसंरचना कार्यक्रमों की सबसे कमजोर कड़ी होती है, अब भी स्थानीय संस्थाओं की तकनीकी क्षमता और वित्तीय संसाधनों पर काफी निर्भर हैं। व्यय की प्रवृत्तियां भी क्रियान्वयन की असमान गति को उजागर करती हैं। यद्यपि 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में मिशन हेतु लगभग 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे,जो इसके पिछले वर्ष के समान ही है, लेकिन वास्तविक खर्च इससे कहीं कम रहा। 2025-26 के संशोधित अनुमान में इसे घटाकर लगभग 17,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, जबकि 2024-25 में वास्तविक व्यय लगभग 22,615 करोड़ रुपये रहा था।

ये आंकड़े संकेत देते हैं कि क्रियान्वयन में बाधाएं,खरीद में देरी और क्षमता की सीमाएं आवंटित धन के उपयोग की गति को धीमा कर रही हैं। इस संदर्भ में,कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू करना और उसका पुनर्गठन पहले की प्रशासनिक और परिचालन चुनौतियों को दूर करने का अवसर माना जा सकता है ताकि सार्वजनिक धन का अधिक कुशल उपयोग हो सके। समान रूप से महत्त्वपूर्ण चिंता जल की उपलब्धता से भी जुड़ी हुई है। भारत पहले से ही दुनिया के सबसे जल संकट वाले देशों में से एक है, जहां कई क्षेत्रों को गिरते भूजल स्तर और बिगड़ती जल गुणवत्ता का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जल आपूर्ति में भूजल अब भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ग्रामीण भारत में पेयजल की मांग का 85 फीसदी से अधिक और सिंचाई की मांग का 60 फीसदी से अधिक भूजल स्रोतों से पूरा होता है। जल-अभाव वाले क्षेत्रों में भूजल पर बढ़ती निर्भरता दीर्घकालिक जल सुरक्षा को कमजोर कर सकती है, जब तक कि इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित न किया जाए।

युद्ध तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव

सुभाष बुड़ावन वाला,रतलाम.मप्र

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है, उसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ता है। ऐसे समय में देश के भीतर रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी का बढ़ जाना इस बात का संकेत है कि संकट की घड़ी में कुछ लोग केवल मुनाफा कमाने के अवसर तलाशते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इससे आम जनता की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हाल ही में विभिन्न शहरों में प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडरों की अवैध जमाखोरी पकड़ी गई। कई लोगों ने अपने गोदामों और घरों में दर्जनों सिलिंडर छिपाकर रखे थे,ताकि बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में कुछ प्रभावशाली लोग और स्थानीय स्तर के नेता भी शामिल पाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि कालाबाजारी केवल छोटे स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे संगठित नेटवर्क भी काम करता है। रसोई गैस की कालाबाजारी का एक बड़ा कारण प्रशासनिक लापरवाही और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी मानी जाती है। जब निगरानी तंत्र कमजोर होता है या नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया जाता, तब ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है। कई बार पुलिस और संबंधित विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं करते, जिससे जमाखोरों को खुलेआम काम करने का अवसर मिल जाता है। यही वजह है कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बावजूद इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाता। कानून के अनुसार जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भारी जुर्माना और तीन महीने से लेकर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में ऐसे कड़े दंड बहुत कम देखने को मिलते हैं। अधिकांश मामलों में आरोपी कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर बच निकलते हैं या मामूली जुर्माना देकर छूट जाते हैं। इससे यह संदेश जाता है कि अपराध करने का जोखिम कम है और लाभ अधिक, जो कालाबाजारी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इस समस्या में आम जनता की भूमिका भी पूरी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती। कई लोग संकट के डर से आवश्यकता से अधिक गैस सिलिंडर जमा करने लगते हैं या अधिक कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इससे बाजार में कृत्रिम मांग पैदा होती है और जमाखोरों को अपने मुनाफे का रास्ता मिल जाता है। यदि उपभोक्ता संयम और जागरूकता दिखाएं तथा अधिक कीमत पर गैस खरीदने से इंकार करें, तो कालाबाजारियों की हिम्मत काफी हद तक टूट सकती है। समस्या के समाधान के लिए सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना होगा। गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, डिजिटल ट्रैकिंग लागू करने और शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी करने की जरूरत है। साथ ही दोषी अधिकारियों और मुनाफाखोरों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। जब तक कानून का सख्ती से पालन नहीं होगा और समाज में नैतिक जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक ऐसी आपात परिस्थितियों में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेगी!

ग्लोबल वार्मिंग नए तेवर में,धरती की उष्णता और तीव्रता से बढ़ेगी

ग्लोबल वार्मिंग का खतरा वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया है और ऐतिहासिक तौर पर पिछले दो से तीन सौ वर्षों की तुलना की जाए तो बीते कुछ वर्षों में धरती का तापमान आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कुल मिलाकर 10 से 15 वर्ष ही शेष है। वैज्ञानिकों की यह बातें और रहस्योद्घाटन मानवता को डराने वाला जरूर है पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके उपायों की जो घोर अनदेखी की जा रही है वह अत्यंत चिंतनीय है। मानवता के लिए अत्यंत खतरनाक भी है...

संजीव ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़

ग्लोबल वार्मिंग या धरती की उष्णता की जब भी कहीं चर्चा होती है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिका,इंग्लैंड और तमाम यूरोपीय देश जिसमें फ्रां,इटली,कनाडा इजरायल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा पश्चिम एशिया के धनवान देश में इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा के कारण जहां वातानुकूलित मशीने, कल कारखाने,मोटर वाहन एवं अन्य ऐसी मशीने जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं दूषित हवा वायुमंडल में फैलती है ही बड़े जिम्मेदार होते हैं और इसका खामियाजा दक्षिण एशिया दक्षिण अफ्रीका और छोटे-छोटे देश को उठाना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के उपाय के लिए आयोजित बड़े-बड़े सम्मेलनों में यही बड़े देश अपनी जिम्मेदारी छोटे-छोटे देश पर डालकर निवृत्ति हो जाते हैं। जबकि सारा किया कराया इन्हीं देशों का होता है और छोटे-छोटे देश को इसके लिए नियमन पालन की जिम्मेदारी सौंप जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में ही जहां गरीबी ने अपना परचम फैला रखा है। शहरों में पेट्रोल ,डीजल, केरोसिन से चलने वाली गाड़ियों और वातानुकूलित यंत्रों याने ए,सी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने से वातावरण में उष्णता बढ़ते जा रही हैद्य इसके अलावा वनों का विनाश एक भयानक समस्या के रूप में देश में फैलता जा रहा हैद्य अंधाधुंध फैक्ट्रियों एवं मशीनों के उपकरणों से निकलने वाले धुंए से वातावरण विषैला बनाकर मनुष्य और जीव जंतुओं का जीना दूभर कर दिया है। वनों की कटाई के साथ-साथ कंक्रीट के जंगल धीरे-धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे हैं, ऐसे में शुद्ध वायु और और तापमान में आश्चर्यजनक बदलाव जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा ऋतु के परिवर्तन एवं बारिश में न्यूनता आने से धरती के तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी के चलते देश के कई शहरों में तापमान 48 से 50 सेल्सियस होने के कारण पशु पक्षी एवं मनुष्य की हीट स्ट्रोक से मृत्यु हुई हो जाती है। पानी की कमी तथा शरीर में डिहाइड्रेशन से लोगों की तथा वन्य पशुओं की लगातार मृत्यु हो रही है।

ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य के लिए खतरा है बल्कि जीव-जंतुओं समुद्र मैं पाए जाने वाले जीवो के लिए भी यह अत्यंत विषैला तथा खतरनाक हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जीवाश्म ईंधन के दशक ने एवं जलने से ग्लोबल वार्मिंग का तापमान तेजी से बढ़ा है एवं पूरी पृथ्वी जीवाश्म ईंधन के जलने से तेजी से धड़क रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी तथा दिए गए प्रमाण के बाद भी अनेक देश जो कार्बन उत्सर्जन के बड़े जिम्मेदार हैं,जीवाश्म ईंधन की इस्तेमाल को कम करने या खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत खत्म होने की बात तो दूर है कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और तो और इसके आसार भी निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों जिसमें अमेरिका ब्रिटेन के अलावा 32 देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन एवं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं,सम्मेलन कर इस पर चिंता जरूर जताई है पर इसमें स्पष्ट तौर पर अमेरिका,ब्रिटेन,जापान चीन,रूस की दादागिरी दिखाई देती है,यह छोटे गरीब देशों पर सारी जिम्मेदारी लादने का काम कर रहे हैं ।विश्व के कुल देशों में से लगभग 50 देश ऐसे हैं जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर पृथ्वी को धधकाने के कार्य का 60% तक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन इन देशों को ग्लोबल वार्मिंग की चिंता की बजाए विकासशील देश एवं गरीब देशों पर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दोषारोपण कर के अपनी इतिश्री कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण चिंतन जितने भी सम्मेलन हुए हैं इसमें बड़े देशों की नीति एवं दादागिरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चीन जो सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक देश है उसने पर्यावरण पर हुए सम्मेलनों में हिस्सेदारी तो दूर उसकी तरफ ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने चेतावनी दी है कि धरती के तापमान की वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43% से 50% तक कटौती करनी होगी। 2010 से लेकर 2021 तक दुनिया का औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानव इतिहास में

सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जो सर्वाधिक खतरे के निशान से भी ऊपर है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन के वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को लगभग शून्य पर लाना होगा, और इस कार्य के लिए पूरी दुनिया को ऊर्जा क्षेत्र में बड़े और कार्यकारी बदलाव लाने होंगे,इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के उपभोग में भारी कमी भी लानी पड़ेगी। विगत 3 वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों में जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा साथी स्टोरेज बैटरी की लागत में आश्चर्यजनक गिरावट आई है जो लगभग गैस तथा कोयले की कीमत के बराबर हो गए हैं। कार्बन उत्सर्जन अभी 54% अधिक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो दुनिया के सब अमीर देश अकेले विश्व के कुल गैस उत्सर्जन के लिए बड़े जिम्मेदार पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले आठ दस सालों में अपने गैस उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50% से कम नहीं करती है तो वर्ष 2050 तक उसे शून्य स्तर पर लाना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में सहित 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। 1990 से लेकर 1920 तक भारत के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक में 175% की बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 2021 के बीच देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा 17 फ़ीसदी बढ़ी है, राहत की बात यह है कि अब भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। देश में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 11% की है, भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट का योगदान 74% है। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोका नहीं गया और जीवाश्म ईंधन के उपयोग की रफ्तार यही रही तो भारत सहित विश्व के अधिकांश देश अपनी धरती को बचाने में सक्षम नहीं होंगे।

अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : खड़ीबोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रणेता

प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा, उ.प्र.

हिंदी साहित्य इतिहास का आधुनिक काल खंड भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से माना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर न केवल स्वयं खड़ीबोली में रचनाएं लिखीं बल्कि अन्यान्य लेखकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी किया। पत्र-पत्रिकाओं का संपादन करते हुए लेखकों को अभिव्यक्ति हेतु अवसर और मंच उपलब्ध कराया। फलतः खड़ीबोली में कविताएं और गद्य रचनाओं का लेखन होने लगा। कविता लेखन को ब्रजभाषा से निकाल कर खड़ीबोली हिंदी के क्षेत्र में अंकुरित-पुष्पित करने का महनीय कार्य जिस व्यक्तित्व ने किया और खड़ीबोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य 'प्रिय प्रवास' लिख साहित्य सागर को समृद्ध किया, वे लेखनी के धनी अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' थे, जिनका निधन देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के पांच महीने पहले 16 मार्च, 1947 को निजामाबाद (आजमगढ़) हुआ था। मां भारती के साधक हरिऔध की पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण समीचीन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल, 1865 को आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद गांव में हुआ था। पिता पं. भोला सिंह उपाध्याय और माता रुक्मिणी देवी का प्यार-दुलार पाते शिशु की किलकारियां घर-आंगन में गूंजती रहतीं। जब वह केवल पांच वर्ष के थे, तब उनके चाचा ने फारसी सिखाना आरम्भ कर दिया था।? बाद में पाठशाला जाना हुआ और मिडिल कक्षा उत्तीर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु काशी के प्रसिद्ध क्वींस कालेज में प्रवेश लिया। पर बनारस की जलवायु बालक अयोध्या को रास न आई, और वह अस्वस्थ हो गये। उचित चिकित्सा से वह स्वस्थ तो हो जाते किंतु जल्दी ही पुनः अस्वस्थ हो जाते। इस कारण परिवार ने काशी से गांव निजामाबाद बुला कर घर पर पढ़ाई-लिखाई का समुचित प्रबंध कर दिया। उनमें सीखने का भाव कूट-कूट कर भरा था, शिक्षक द्वारा सिखाए पाठ वह यथाशीघ्र सीख-समझ लेते। इस तरह घर पर अध्ययन करते हुए संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त कर लिया। वर्ष 1883 में मिडिल स्कूल निजामाबाद में हेडमास्टर नियुक्त हो गये और अगले ही वर्ष 1884 में निर्मला कुमारी के साथ विवाह बंधन में बंध दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। बचपन से ही प्रकृति की स्नेह-छांव मिली थी,घर पर ग्रंथों का पठन-पाठन होने से बालक अयोध्या में भी साहित्यिक अभिरुचि पनपने लगी और वह ब्रजभाषा में कविता करने लगे थे? अध्ययन के प्रति रुचि और जिज्ञासा के चलते खूब पढ़ते। आगे 1889 में आप राजस्व विभाग में परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो पद पर नियुक्त हुए और लगभग चार दशक तक कार्य करके 1932 में अवकाश ले लिया। इसी मध्य आप साहित्य के क्षेत्र में एक चर्चित व्यक्तित्व बनकर उभरे। 1914 में खड़ीबोली हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य 'प्रिय प्रवास' प्रकाशित हुआ और आपकी कीर्ति कौमुदी से हिंदी साहित्याकाश जगमगा उठा। इस महाकाव्य कृति पर आपको कालांतर में तत्कालीन प्रसिद्ध सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ,जिससे आपकी यश पताका देश में चतुर्दिक फहरने लगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1924 के आयोजन में आपको सभापति बनाकर गौरवान्वित हुआ। आगे आपको विद्या वाचस्पति एवं कवि सम्राट की मानद उपाधि भेंटकर साहित्य समाज ने आनन्द का अनुभव किया।

अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के रचना संसार की सीमा व्यापक है। आपके लेखन का आरम्भ ब्रजभाषा में कविता करने से अवश्य हुआ पर आप उस धारा से निकल खड़ीबोली हिंदी के प्रांजल प्रवाह में सम्मिलित हो गये। ठेठ हिन्दी का ठाठ और अधखिला फूल जैसे उपन्यास भेंट कर हिंदी का गौरव बढ़ाया तो रुक्मिणी परिणय और प्रद्युम्न विजय प्रभृति नाटकों की रचना की। लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करते हुए लोकभाषाबोली का रस ग्रहण कर चोखे-चौपदे तथा चुभते-चौपदे,रस कलश आदि रचनाएं लोक के हाथों में अर्पित की। लेकिन उनकी ख्याति प्रिय प्रवास के रचनाकार के रूप में ही रही। 17 सर्गों में विभाजित 'प्रिय प्रवास' में राधा-कृष्ण के प्रेम एवं वियोग का अद्भुत वर्णन हुआ है जो पाठक के हृदय को आर्द्र कर देता है। सीता-राम के जीवन चरित्र का चित्रांकन 18 सर्गों में आबद्ध 'वैदेही वनवास' में मिलता है जो 1940 में छपा। वर्ष 1937 में मुद्रित 15 सर्गों का महाकाव्य 'पारिजात' एक उल्लेखनीय कृति है। मौलिक लेखन के साथ ही हरिऔध जी ने अनुवाद के क्षेत्र में भी उपस्थिति दर्ज कराई और मर्चेंट आफ वेनिस का खड़ीबोली हिंदी में अनुवाद किया-वेनिस का बांका, जो खूब सराहा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भाषा में विविधता है। एक ओर वह संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग करते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह उर्दू-फारसी के शब्दों से भी खूब दोस्ती निभाते हैं। देसज शब्द और लोकोक्तियों के प्रयोग से वह पाठक को अपनी माटी की महक से परिचित कराते हैं तो ब्रजभाषा के प्रयोग से मधुरता और कोमलता का दर्शन भी कराते हैं। प्रकृति चित्रण से दृश्यों की सजीव प्रस्तुति मन को रससिक्त करती है। कविता के पारम्परिक संस्कृत भाषा के इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित,शिखरिणी,मदाक्रांता छंदों पर काव्य रचना करते हैं तो छप्पय,दोहा,कवित्त और सवैया को भी नहीं भूलते। इसीलिए पाठक उनकी रुचिर रचनाओं में रमता चला जाता है। वर्ष 1932 में आपने कानूनगो पद से अवकाश लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अवैतनिक प्राध्यापक पद का कार्यभार ग्रहण किया और 1942 में सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात आप अपने गांव निजामाबाद आ गये और निरंतर लेखन साधना में सक्रिय रहे। अपनी जन्मभूमि में ही 16 मार्च,1947 को आपने अंतिम सांस ले नश्वर देह मां भारती के चरणों में समर्पित कर दी। हिंदीखडी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में सदा-सर्वदा स्मरण किए जाते रहेंगे। भारत सरकार ने हरिऔध जी पर एक विशेष डाक टिकट आजमगढ़ डाक प्रदर्शनी के दौरान 2 मार्च, 2013 को जारी किया था, जो स्मरणीय है।

शशश !! चुप कलम चुप! विराम दे अपनी कलम को...

डॉ वीना तन्वी
नागपुर,महाराष्ट्र

शीर्षक देखकर, पढ़कर या सुन कर बड़ा अजीब लगा होगा ना पाठकों आपको, सच तो कह रही पाठकों कलम की बढ़ती राह में भी है कुछ मर्यादित रेखाएं हैं जो हमें लिखने से पहले सोचने समझने पर पहले विवश करती और वो मर्यादित रेखा हम लेखकों,पत्रकारों को पहले दूरदृष्टी डाल भविष्य के बारे में सोचने पर विवश करती। अब आप पाठक सोच रहे होंगे कि कलम लेखक की,सोच,भावना,शब्द लेखक के फिर लेखक विवश कैसे हो सकता है वो तो जो चाहे वो लिख सकता है? भला लेखक या पत्रकार को रोकने वाला कौन हो सकता है?

क्यों पाठकों आप यही सोच रहे हैं ना? परंतु पाठकों आपकी सोच लेखक के प्रति सम्मानिय है, आप लेखक से सच को पारदर्शीता की तरह परोसने की इच्छा भी रखते हैं। आप चाहते हैं हर कोई साहित्यकार व पत्रकार सच को बखूबी शब्दों में परोस कर हकीकत भरा आईना दुनिया को दिखाए। आपकी सोच बिल्कुल सही है पाठकों परंतु हम लेखकों के कलम के आगे एक मर्यादा भरी रेखा खिंची होती है यदि हमने उस मर्यादा रेखा को पार कर लिया या पार करने की कोशिश मात्र भी की तो हमारी कलम के उड़ते परों को इस तरह काट कर धराशाई कर दिया जाएगा की कलम फिर अपने भावना, शब्दों संग उड़ान या तो भर ही नहीं पाएगा या उड़ेगी कलम तो फिलहाल जो पंख काटे गये थे उससे अधिक बढ़कर और बुरा होते हुए कलम या कलम के मालिक के ही कब टुकड़े-टुकड़े कर बिखेर दिए जाएं पता भी नहीं चलेगा। अब आप पाठक ये सोच रहे होंगे भला ये कैसे संभव है और कौन क्षति पहुंचा सकता है किसी पत्रकार या लेखक को? और कौन सी ऐसी मर्यादित रेखा है लेखक के लिए? क्यों यही सोच रहे ना पाठकों? चलो आपको और अधिक कशमोकश में नहीं उलझाऊंगी और हमारी लेखन की मर्यादित रेखा के बारे में बताऊंगी।? हुआ यूं कि अपनी तीन साल पुरानी एक पोस्ट का अपडेट जब मेरे फेसबुक पेज पर आया तो मेरी यादें ताजा हो गई और बहुत खुश थी मैं, मैंने वही तीन साल पुरानी पोस्ट की अपडेट अपने द्वारा इस्तेमाल की जा रही हर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर साझा की,जिसमें से एक प्लेटफार्म है ट्विटर फिर क्या था वहां के एक सम्मानित आईडी से जुड़ भाई ने मुझे मेरे लेखक होने और समाज के प्रति जागरूक रह कर सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिये जागरूक किया, तब मैंने बहुत ही सम्मान से उनके मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व से भरे विशेष विषय के बारे में पूछा की आखिर वह कौन सा मुद्दा कलम के माध्यम से उठाना चाहते थे। जब भाई ने मुझे मन में चल रहे मुद्दे के बारे में बताया तो पहले मैंने सोचा और फिर उन्हें समझाया कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर खामोश रहा जाए तो उसमें लेखक या पत्रकार की ही भलाई होती है क्योंकि कुछ मुद्दे पहले सामान्य होते-होते वह राजनैतिक के हत्थे चढ़ जाते हैं और राजनैतिक की सूली पर यदि कोई मुद्दा चढ़ जाए और उसमें कोई भी आम लेखक हस्तक्षेप करे तो उसमें आम जनता या पाठक तो साईड हो जाएंगे परंतु लेखक/पत्रकार को तमाम गहमागहमी में उलझाकर रख दिया जाएगा ये एक लेखक ही जानता है। समाज में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्होंने किसी विशेष मुद्दे को या व्यक्ति विशेष को समाज के सामने ला कर रख दिया तब उन पत्रकार का घने अंधेरे में ही क्या हश्र किया गया ये न्यूज़ कवरेज के माध्यम से ही सुर्खियों में देखा गया है। चर्चित न्यूज़ एंकर जो टेलीविजन के विशेष खबरों के चैनल से जुड़े थे आज भी वो जुड़े हैं परंतु उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें पूरी तरह से प्रताड़ित कर तोड़ दिया गया और उन्हें उस चैनल से हटाकर दूसरे राज्य के चैनल पर कार्य हेतु लगाया गया , हालांकि आज वो पुनः उसी चैनल में नज़र आ रहे हैं। खुशी बहुत है कि वह पुनः खबरों में अपनी वही बेहतरीन जगह बना पाए जो पहले थी परंतु एक पत्रकार न्यूज़ एंकर जब कभी मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले वही कंपनी पीछे हट अपना पल्ला झाड़ती जिस कंपनी से वह पत्रकार जुड़ा हुआ है। इसलिए भविष्य व परिवार को ध्यान में रखते हुए ही एक पत्रकार या लेखक या न्यूज़ एंकर सभी वो सोच समझ के लिखना पड़ता है। हां वो पत्रकार या अन्य खुलकर बेधड़क, निडर हो लिख सकते जिनके सर पर ऊंचे पदों आसीन लोगों की छत्रछाया होगी, जिनके सिंहासन के नीचे बैठ वो महफूज़ होकर लिख सकते, जिनसे ऊंचे पदों आसीन लोग भी लिखवाते विपक्ष के खिलाफ और आश्वस्त करते हम हैं ना तू लिख बस। बाकी आम पत्रकार, लेखक व न्यूज़ एंकर ने अगर लिख दिया और कोई बात किसी को चुभ गई तो उसे खींच के कटघरे में उतार दिया जाता और साक्ष्य मांगे जाते।

कविता

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़ छग

चलो बहाना खोजते हैं...

बैठे बैठे हम यूं ही सबको कोसते हैं,
चलो कुछ न करने का बहाना खोजते हैं,
अपने मन को अपनों के लिए
हम क्यों नहीं खींचते हैं,
जैसे प्यार से अपने खेतों में पानी सींचते हैं,
आओ विचारों पर चलना सीखें,
औरों संग खुद भी संभलना सीखें,
क्या हम अपना गौरवशाली इतिहास
लोगों को बता नहीं सकते,
हताशा को दूर रख
एक छत के नीचे आ नहीं सकते,
जब जरूरत हो तब
साथ न चलने का फसाना खोजते हैं,
चलो कुछ न करने का बहाना खोजते हैं,
हम भूल जा रहे हैं कि
विरोधी कदम दर कदम तैयारी कर रहे हैं,
छलने को हमें अय्यारी कर रहे हैं,
हम मस्त हो हर नशे में डूबे जा रहे हैं,
भांग गांजा शराब और
चमत्कारिक प्रसाद खा रहे हैं,
झूठ मूठ किसी और के गीत गाये जा रहे हैं,
मानसिक दिवालिया हो अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं,
बहाने भी इतने अच्छे कि
समाज को लौटाने में टालमटोल कर रहे हैं,
दे सकते हैं चंद कलम किसी जरूरतदार को
पाखंडों को अपना मस्तिष्क में
पेट्रोल संग चिंगारी धर रहे हैं,
अच्छा हुआ कि बुद्ध ने,
ज्योतिबा,रैदास,कबीर और भीम जैसे प्रबुद्ध ने,
पेरियार, ललई, जगदेव बाबू, छोटूराम ने,
राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले
मान्यवर कांशीराम ने,
यदि कुछ न कर बहाने खोजे होते,
तो पड़े रहते अपनी किस्मत पर रोते,
कुछ न कर अपनों को नोचते हैं,
अब भी कह रहे चलो बहाना खोजते हैं।

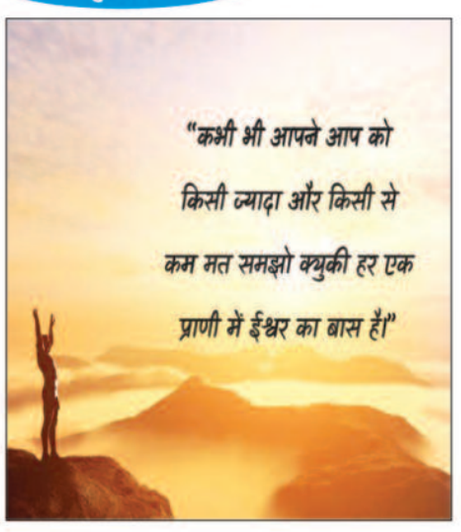

सुविचार

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

गौधाम योजना को लेकर भाजपा सरकार पर कांग्रेस का हमला

■ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील सिंह बोले...गोठान योजना को नया नाम देकर किया जा रहा प्रचार

■ मंच पर तालियां और जमीन पर समस्या-किसानों और गौवंश की स्थिति पर उठाए सवाल

अंबिकापुर/बलरामपुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की जा रही तथाकथित 'गौधाम योजना' को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, कांग्रेस ने इस योजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार जिस योजना को बड़े शोर-शराबे के साथ नई पहल बताकर प्रस्तुत कर रही है, वह वास्तव में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गोठान योजना का ही बदला हुआ स्वरूप है, उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलकर,नए बोर्ड लगाकर और बड़े स्तर पर प्रचार कर किसी योजना को नई नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार वास्तव में गौ सेवा के लिए गंभीर है तो उसे जमीनी स्तर पर व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

वर्चुअल कार्यक्रम से होगा शुभारंभ

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया जा रहा है,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,मंत्री राम विचार नेताम तथा छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रांत अध्यक्ष विशेश्वर पटेल की उपस्थिति में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय,कोनी बिलासपुर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसी क्रम में बलरामपुर जिले के ग्राम देवीगंज, विकासखंड रामचंद्रपुर में 'सुरभि गौधाम' का

भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है, इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति तय की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनि निकुंज,गौ सेवा आयोग के जिला अध्यक्ष आशीष केसरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव,भाजपा जिला महामंत्री भानु दीक्षित सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे।

कांग्रेस का आरोप

नई योजना नहीं, पुरानी का नया नाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील सिंह ने कहा कि जिस गोठान योजना को भाजपा ने पूर्व में लगातार राजनीतिक रूप से निशाना बनाया था, आज उसी योजना के ढांचे को नया नाम देकर फिर

से प्रस्तुत किया जा रहा है,उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि जिस योजना को वर्षों तक 'असफल' बताकर आलोचना की गई,उसी के मॉडल को अब 'महत्वाकांक्षी योजना' बताकर प्रचारित किया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया अगर गोठान योजना इतनी खराब थी तो उसी मॉडल को फिर क्यों अपनाया जा रहा है? और अगर वह योजना अच्छी थी तो उसे पहले राजनीतिक रूप से बदनाम क्यों किया गया?

जमीनी स्थिति पर उठाए गंभीर सवाल

सुनील सिंह ने कहा कि राज्य के कई गांवों में गोठानों की स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है,उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पहले गोठानों में पशु,चारा और गतिविधियां दिखाई देती थीं, वहां अब कई स्थानों पर केवल टूटे शेड,बंद दरवाजे और औपचारिक व्यवस्थाएं ही बची हैं, उन्होंने कहा कि कई जगह गोठान केवल फोटो खिंचवाने और सरकारी कागजों में दर्ज रहने तक सीमित हो गए हैं।

आवारा पशुओं से किसान परेशान

उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर बनी हुई है,कई किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात-रात भर खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। फसल नुकसान की समस्या बढ़ती जा रही है,लेकिन इस दिशा में कोई ठोस समाधान दिखाई नहीं देता, उनका कहना था कि गौ सेवा के नाम पर बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान अभी भी अधूरा है।

मंच पर तालियां,जमीन पर समस्या

कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है कि मंच पर तालियां ज्यादा सुनाई देती हैं और जमीन पर समस्याएं ज्यादा दिखाई देती हैं, उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने और बड़े स्तर पर प्रचार करने से समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक जमीनी स्तर पर मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक ऐसी योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा।

गौ सेवा या राजनीतिक प्रचार?

सुनील सिंह ने कहा कि गायों के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन गौवंश के संरक्षण और किसानों को राहत देने के लिए ठोस व्यवस्था बनाना ज्यादा जरूरी है, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में कई जगह गौ सेवा से ज्यादा गौ प्रचार दिखाई दे रहा है, उनका कहना था कि केवल कार्यक्रमों और उद्घाटनों से गौ सेवा संभव नहीं है। इसके लिए स्थायी व्यवस्था,पर्याप्त संसाधन और प्रभावी निगरानी जरूरी है।

सरकार से की पारदर्शिता और सुधार की मांग-सुनील सिंह ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गौ सेवा के लिए गंभीर है तो उसे योजनाओं का नाम बदलने के बजाय उनकी कार्यप्रणाली को सुधारने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने कहा कि गौवंश की सुरक्षा, किसानों की समस्याओं का समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ही किसी भी ऐसी योजना की वास्तविक सफलता होगी।

जनता पूछ रही है बड़ा सवाल

उन्होंने कहा कि आज जनता यह सवाल पूछ रही है, क्या गौ सेवा केवल नए नाम, नए बोर्ड और नए कार्यक्रमों से हो जाएगी? या फिर वास्तव में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे गौवंश सुरक्षित रहे, किसानों को राहत मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो?

अंत में...

कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में गौवंश और किसान दोनों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है,सरकार को चाहिए कि वह योजनाओं के प्रचार के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दे,ताकि गांवों में वास्तविक परिवर्तन दिखाई दे, अन्यथा जनता के बीच यह धारणा मजबूत होती जाएगी कि यह पूरा प्रयास गौ सेवा से ज्यादा राजनीतिक पुनःपैकेजिंग है।

सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो डालकर कर रहा था ब्लैकमेल,यूपी से आरोपी गिरफ्तार

शादी के लिए बना रहा था दबाव,शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक फोटो-वीडियो अपलोड कर ब्लैकमेल करने और शादी के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती को लगातार धमकी दे रहा था,जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पहचान उत्तरप्रदेश निवासी चंद्रमौली तिवारी से एक घरेलू कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल के माध्यम से बातचीत होने लगी। इसी दौरान आरोपी ने धोखे से युवती की सोशल मीडिया आईडी हासिल कर ली और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लिया। इसके बाद आरोपी ने युवती

की बिना अनुमति के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। साथ ही शादी से इनकार करने पर मारपीट करने की धमकी भी दे रहा था। लगातार धमकियों से परेशान होकर युवती ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी चंद्रमौली तिवारी (27) पिता अमरनाथ तिवारी, निवासी ग्राम तिवारी नगवा, थाना गगहा, जिला गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 79 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहा था वाहन,चालक गिरफ्तार

एक ही नंबर से दो जगह चल रही थी गाड़ी, धान परिवहन के दौरान मामला उजागर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने के मामले में लखनपुर पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि एक ही नंबर प्लेट से दो अलग-अलग स्थानों पर वाहन संचालित किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार खाद्य निरीक्षक सतपाल सिंह कंवर ने थाना लखनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वाहन क्रमांक सीजी 07 बीएस 0366 के नाम से दो अलग-अलग स्थानों पर वाहन चलने की जानकारी राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से अलर्ट मैसेज के माध्यम से मिली थी। जिला खाद्य अधिकारी सरगुजा के निर्देश पर जांच की गई। इस दौरान धान खरीदी केंद्र जमगला में धान परिवहन कार्य में लगे उक्त वाहन को 6 फरवरी 2026 को पकड़कर थाना लखनपुर लाया गया और पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। जांच के दौरान वाहन चालक राम मानिकपुरी से वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मामले की जानकारी

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंबिकापुर को भेजी गई। आरटीओ की जांच में सामने आया कि वाहन पर लगा सीजी 07 बीएस 0366 नंबर फर्जी है। वाहन पर दो अलग-अलग चेसिस नंबर भी अंकित पाए गए। ऑनलाइन जांच में एक चेसिस नंबर किसी वाहन से पंजीकृत नहीं मिला, जबकि दूसरे चेसिस नंबर पर सीजी 15 डीजे 9799 नंबर का वाहन पंजीकृत पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि वास्तविक वाहन क्रमांक सीजी 15 डीजे 9799 है और उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था।

चालक गिरफ्तार, वाहन मालिक फरार

पुलिस ने मामले में चालक राम मानिकपुरी (27) निवासी हुसैनी नगर महामाया मंदिर, अंबिकापुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने की बात स्वीकार की है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन मालिक फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लखनपुर उपनिरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उपनिरीक्षक निशिकांत एक्का, प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी तथा आरक्षक जगेश्वर बघेल, दशरथ राजवाड़े और पैमाशी राम की सक्रिय भूमिका रही।

आंगनबाड़ी केंद्र में लगा 'अर्ली चाइल्डहुड केयर मेला',बच्चों के समग्र विकास पर दिया गया जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-सरगुजा द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (ग्रामीण) अंतर्गत सेक्टर मेंड्राकला स्थित लब्जी पंचायत भवन में 'ईसीसीई मेला/बाल मेला' का आयोजन किया गया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास,पोषण संबंधी जागरूकता तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा को समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में सीडीपीओ बेस्था तिर्की, सेक्टर सुपरवाइजर अनीता सिंह,महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी,समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,बीडीसी श्रीमती शोभा बाई,सरपंच श्रीमती अनीता बाई भगत,उपसरपंच,ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि,अभिभावक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। मेले में बच्चों के सीखने और विकास को प्रदर्शित करने के लिए कुल सात विषयगत लर्निंग कॉर्नर/स्टॉल लगाए गए। इनमें पोषण आहार,आओ मिलान करें,कहानी और कविता,आओ रास्ता खोजें, आवा काहिं काहिं बनाबो,छूओ,सूंघो और पहचानो तथा आवा खेलबो आऊ खिलाबो जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक,रचनात्मक और संवेदनात्मक विकास से जुड़ी जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक स्टॉल पर विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने लगभग 10-10 मिनट तक प्रत्येक लर्निंग कॉर्नर का अवलोकन किया। इस दौरान पोषण,स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों में गतिविधि आधारित प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त बनाने के साथ-साथ समुदाय को बच्चों के पोषण और विकास के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों से बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

स्काई वॉचिंग कैम्प में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने ली खगोल विज्ञान की बुनियादी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम साइंस कॉलेज अंबिकापुर में आयोजित स्काई वॉचिंग और स्टार गेजिंग कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया से रूबरू होने का अवसर मिला। कार्यक्रम में करीब 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने टेलीस्कोप के माध्यम से सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति (जुपीटर) और उसके चंद्रमाओं का अवलोकन किया। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) 2.0 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना था। कार्यक्रम का आयोजन 14 मार्च को दिन और रात दोनों सत्रों में किया गया। कार्यक्रम के दौरान तीन टेलीस्कोप की मदद से विद्यार्थियों को आकाश में दिखाई

देने वाले ग्रहों और उपग्रहों को दिखाया गया। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के अध्यक्ष विश्वास मेश्राम ने अपने 150 मिलीमीटर व्यास के टेलीस्कोप से विद्यार्थियों को बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अवलोकन कराया। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सेंटर फॉर बेसिक साइंस के रिसर्च स्कॉलर सुरेश गुप्ता और यशवंत साहू तथा केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के भौतिकी शिक्षक राजू गुप्ता ने भी विद्यार्थियों को खगोलीय पिंडों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विज्ञान गीत के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद अतिथियों ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल ने विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व और नई खोजों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच और नवाचार आज के समय की आवश्यकता है। तकनीकी सत्र में विद्यार्थियों को टेलीस्कोप की कार्यप्रणाली और खगोल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने बारी-बारी से टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रहों और उपग्रहों का अवलोकन किया। रात के समय आसमान साफ रहने से विद्यार्थियों को बृहस्पति ग्रह की डिस्क और उसके चंद्रमा स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रिजवान उल्ला ने सभी अतिथियों और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने भी इस प्रकार के विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों को हर वर्ष आयोजित करने की मांग की। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. के.के. सहारे, सरगुजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम, वरिष्ठ इंजीनियर सुमित सिंह सहित कई विज्ञान कार्यकर्ताओं और महाविद्यालय के शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की बैठक में 21 सूत्रीय एजेंडे पर बनी रणनीति

अधिकारों की लड़ाई एक मंच से लडने का निर्णय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठनों की बैठक रविवार को गांधी चौक स्थित दुर्गा शक्ति पीठ में आयोजित की गई। बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर एकजुटता का परिचय दिया और 21 सूत्रीय एजेंडे पर आगे की रणनीति तय की। बैठक में जशपुर,बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी और कोरिया जिलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने माना कि अलग-अलग संगठनों के कारण उनकी मांगों को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया,इसलिए मतभेद भुलाकर एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कविता यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

अधिकारियों द्वारा छोटे-छोटे मुद्दों पर दबाव और प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। वहीं पुष्पा श्रेजल ने कहा कि सरकार को कार्यकर्ता-सहायिकाओं की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही गुणवत्ताविहीन साडियों पर भी सवाल उठाते हुए ऐसी सामग्री का उठाव नहीं करने की बात कही। बैठक में सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्ता-सहायिकाओं के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने और उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने की मांग भी उठाई गई।

कांग्रेस की वर्चुअल बैठक,विधानसभा घेराव को सफल बनाने बनाई रणनीति

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से रायपुर पहुंचने का किया आह्वान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा बचाव संग्राम और संगठन को वार्ड, पंचायत व बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विशेष रूप से जुड़े और संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने 17 मार्च को रायपुर में आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से कम से कम दो वाहन तथा फ्रंटल संगठनों से प्रत्येक ब्लॉक स्तर से एक वाहन में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक एकता कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना चाहिए। जिला प्रभारी के. शफी अहमद ने कहा कि मनरेगा बचाव संग्राम केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस आंदोलन को जनसमर्थन दिलाने की अपील की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिहर यादव ने कहा कि बलरामपुर जिले से रायपुर की दूरी अधिक होने के बावजूद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम,डॉ. अजय तिर्की, राजेन्द्र तिवारी, विजय पैकरा,अजय गुप्ता,राजीव सिंह, हरीश मिश्रा सहित कई पदाधिकारियों ने अपने सुझाव भी रखे।

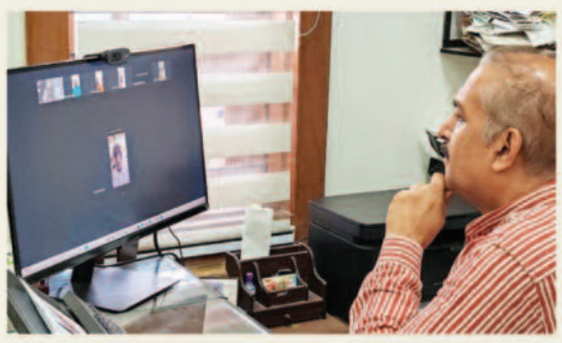

सोनहत में स्वास्थ्य सेवाओं का नया सवेरा...स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह का 'एक्शन', साल भर बाद बहाल हुई सोनोग्राफी सेवा

लगभग एक वर्ष से बंद पड़ी सुविधा अब फिर शुरू,हर शुक्रवार को मिलेगी जांच की सुविधा

साहब...मेरे पास बैकुंठपुर जाने पैसे नहीं...
सोनहत अस्पताल में सोनोग्राफी बंद
महिला फूट-फूटकर रो पड़ी

चलती व्यवस्था पर ताला!
सोनहत अस्पताल में महीनों से बंद सोनोग्राफी सेवा

'घटती-घटना' की लगातार खबरों के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग

राजन पाण्डेय

सोनहत,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र सोनहत के ग्रामीणों के लिए यह सप्ताह राहत भरी खबर लेकर आया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में पिछले लगभग एक वर्ष से बंद पड़ी सोनोग्राफी सुविधा अब फिर से शुरू होने जा रही है,स्वास्थ्य मंत्री के कड़े निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह की सक्रिय पहल के बाद यह व्यवस्था दोबारा बहाल की गई है, इससे क्षेत्र के ग्रामीणों, खासकर गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह की सक्रियता से मिली सफलता

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मामले का संज्ञान लेने के तुरंत बाद सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थानीय स्तर पर आ रही तकनीकी और मैनपावर की समस्याओं को दूर करने की पहल की, बताया जा रहा है कि सोनोग्राफी मशीन,कक्ष व्यवस्था और विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया गया,डॉ. सिंह ने स्वयं इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अब सोनहत क्षेत्र के मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पताल या निजी केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें और न ही अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़े।

हर शुक्रवार को मिलेंगी सोनोग्राफी सेवाएं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए रोस्टर के अनुसार अब डॉ. खुशबू वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में नियमित रूप से सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करेंगी।

नया रोस्टर- अब प्रत्येक शुक्रवार को डॉ. खुशबू वैद्य सोनहत में अपनी सेवाएं देंगी, सीएमएचओ कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद विभाग ने मशीन और कक्ष की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है, ताकि इस सप्ताह से ही जांच की सुविधा शुरू हो सके।

गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सबसे बड़ी राहत- सोनहत जैसे दूरस्थ क्षेत्र में सोनोग्राफी सुविधा बंद होने के कारण गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी, अक्सर मरीजों को जांच के लिए बैकुंठपुर या निजी सोनोग्राफी केंद्रों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता था, अब स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जताया आभार- सोनोग्राफी सेवा दोबारा शुरू होने की खबर से क्षेत्र में खुशी का माहौल है, ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह के प्रयासों की सराहना की है, लोगों का कहना है कि इससे अब गरीब मरीजों को समय पर जांच की सुविधा मिलेगी और अनावश्यक खर्च से भी बचाव होगा।

घटती-घटना के खबर का बड़ा असर

सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी सेवा लंबे समय से बंद होने का मुद्दा समाचार पत्र 'घटती-घटना' द्वारा लगातार उठाया गया था,समाचार पत्र ने इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया और लगातार खबरें प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया,इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी 'घटती-घटना' ने इस मुद्दे पर सीधा सवाल उठाया,जिसके बाद मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विभाग को सेवा बहाल करने के निर्देश दिए।

प्रमुख बिंदु

- राहत : लगभग एक वर्ष बाद सोनहत में फिर शुरू होगी सोनोग्राफी जांच।
- विशेषज्ञ सेवा : डॉ. खुशबू वैद्य प्रत्येक शुक्रवार को देंगी सेवाएं।
- स्थानीय सुविधा : अब ग्रामीणों को जिला अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- प्रशासनिक सक्रियता : सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना।

इनका कहना है

'हमारा लक्ष्य जिले के अंतिम छोर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। सोनहत में सोनोग्राफी सेवा का पुनः प्रारंभ होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. प्रशांत सिंह
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,कोरिया

क्या राजपुर (RES) विभाग के अनुविभागीय अधिकारी जानू राम सोनवानी ने अपने अधीनस्थ मूल्यांकन अधिकारीयो को लूट की है खुली छूट?

इस लिए चेक डैम कार्य में मनरेगा मजदूरों की जगह मशीन से ढलाई कार्य कराकर मजदूरों के हक में डाला डाका?

इस लिए मूल्यांकन अधिकारी (अभियंता RES) एवं ग्राम पंचायत सचिव ने मिलकर ग्राम चंद्रगढ़ को बनाया कामधेनु गाय?

-सुदामा राजवाड़े-

राजपुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत के ग्राम चंद्रगढ़ नाले में मनरेगा योजना के तहत बने चेक डेम निर्माण कार्य कराया गया है, जागरूक ग्रामीणों ने उक्त चेक डेम निर्माण को लेकर उठाया सवाल,चेक डेम निर्माण कार्य को मनरेगा के तहत कार्य कराया जाना था लेकिन ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जानू राम सोनवानी ने अपने विभागीय सिपहसलार मूल्यांकनअधिकारी को दे रखी है लूट की खुली छूट देकर सिपहसालार मूल्यांकन अधिकारी ने नियम को निर्देशों को ताक में रखकर ग्राम के मजदूरों की पेट में लात मारकर उक्त चेक डैम का कार्य मशीन से कराया गया। ग्राम के कुछ जागरूक ग्रामीण ने हमारे संवाददाता से बताया की चंद्रगढ़ नाले में बने चेक डेम की गुणवत्ता घटिया एवं स्तरहीन तरीके से निर्माण की गई है,साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि शासन ने हमारे गांव के नाले के समीप भूमि धारक किसानों के उन्नति एवं मनरेगा के तहत मजदूरो को मजदूरी मिले इसके लिए नाले में चेक डैम निर्माण कराया गया। लेकिन विभाग के सिपासालार मूल्यांकन अधिकारी के निर्देशन में चेक डैम का कार्य भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया,स्तरहींन सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर संका उत्पन्न हो रही है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग के द्वारा चंद्रगढ़ नाला में लगभग 30 लाख रुपये की लागत से पंचायत में बनाए गए चेक डेम निर्माण कार्य कराया गया हैं। ग्राम पंचायत के ग्रामीण ने बताया की चंद्रगढ़,नाला में जो चेक डेम निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त चेक डैम निर्माण कार्य का विभागीय अधिकारी के सिपहसालार मूल्यांकन अधिकारी के साथ साथ ग्राम पंचायत सचिव के साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार कर अंजाम देकर लुट की राशि बंदरबाट की गई है। मूल्यांकन अधिकारी एवं सचिव को मिले अधिकारों के कारण होता है लूट का यह खेल,ग्रामीण के द्वारा बताई गई बात माने तो बात सही साबित होती है राजपुर अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सह पर दशकों से जमे सिपाह सलार (मूल्यांकन अधिकारी) के मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पंचायत सचिव के द्वारा जीओ टेक रिपोर्ट को सही मानकर गुणवत्ता विहीन कार्य को पूर्ण मानकर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा मुहर लगाकर राशि आहरण कर बंदरबाट कर ली जाती है। अगर ऐसा है तो निःसंदेह माना जा सकता है शासन की इस योजना में बट्टा लगाने में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरईएस जानुराम सोनवानी एवं उनके मूल्यांकन अधिकारी के साथ-साथ पंचायत सचिव की भूमिका पर संदेह पैदा होना लाजमी होता है, जो जांच का विषय है?

उक्त विषय को लेकर राजपुर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (RES) के अनुविभागीय अधिकारी

जानू राम सोनवानी जी से उनके मोबाइल नंबर 70881455 पर चेक डेम के लागत सामग्री एवं मनरेगा संबंधित जानकारी चाहिए तो उनके द्वारा कहा गया कि सोमवार को देखकर बताऊंगा।

प्रशासन ने 58 पटवारियों का किया सामूहिक तबादला

-संवाददाता-

बलरामपुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। जिले में हाल ही में सामने आए अवैध अफीम की खेती के प्रकरण के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने एक साथ 58 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से जिले के कई तहसीलों में लंबे समय से जमे पटवारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर भेजा गया है। वाड्रफनगर,शंकरगढ़, रघुनाथनगर,बलरामपुर सहित कई तहसीलों के पटवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम राजस्व व्यवस्था में कसावट लाने,कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ कर्मचारियों के कारण बन रही प्रशासनिक ढिलाई को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

भाजपा संयुक्त मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न....

मोर्चा की ताकत से संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा : जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। जिला मुख्यालय स्थित मानस भवन में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले भर से विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए, सम्मेलन में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के समन्वय और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्रों पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।

संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प- सम्मेलन में उपस्थित भाजपा जिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय देते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया,कार्यक्रम में विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों

ने अपने-अपने कार्यों,उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी साझा की, सम्मेलन में महिला मोर्चा,युवा मोर्चा, किसान मोर्चा,अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा,ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा सहित सभी मोर्चाओं के पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत:देवेंद्र तिवारी- इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत और रीढ़ हैं,जो जनता के बीच जाकर संगठन को मजबूत बनाते हैं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के निःस्वार्थ प्रयासों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और विकास की राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही है, उन्होंने आगे कहा कि मोर्चा संगठन की शक्ति हैं,और जब मोर्चे सक्रिय होते हैं तो संगठन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, आने वाले समय में सभी मोर्चाओं की समन्वित भूमिका भाजपा को और अधिक मजबूत बनाएगी।

सक्रिय कार्ययोजना पर बनी सहमति

सम्मेलन के दौरान सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने आगामी समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना लागू करने पर सहमति व्यक्त की, सभी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया कि वे जिले में भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे।

फूलों की वर्षा के साथ खेली गई 'फूलों की होली'

सम्मेलन के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह और सौहार्द के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा कर फूलों की होली खेली,इस दौरान पूरे वातावरण में आनंद,प्रेम और एकता की भावना दिखाई दी,कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा,जिससे जिले में सकारात्मक माहौल का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम में रहे उपस्थित...

कार्यक्रम में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यसमिति सदस्य और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे, नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह, जनपद अध्यक्ष आशादेवी सोनपाकर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

पटवारियों के दफ्तर में 'निजी ऑपरेटर' का खेल? किसानों से अवैध वसूली के आरोप

शुल्क नहीं देने पर महीनों चक्कर लगाने को मजबूर किसान,खड़गवां तहसील में उठे गंभीर सवाल...

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां (एमसीबी),15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां तहसील में हल्का पटवारियों की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है,किसानों का आरोप है कि कई पटवारियों ने अपने कार्यालय में निजी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रखे हैं,जो जमीन से जुड़े काम कराने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवस्था अब धीरे-धीरे एक अनौपचारिक लेकिन अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है,जहां पटवारी से सीधे काम कराने के बजाय किसानों को पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दिया जाता है।

ऑपरेटर के बिना नहीं होता काम?- किसानों का कहना है कि जब वे जमीन से जुड़े कार्य जैसे नक्शा निकलवाना,खसरा या बी-1 की प्रति लेना,नामांतरण से जुड़ी जानकारी, सीमांकन या अन्य राजस्व दस्तावेज के लिए पटवारी कार्यालय पहुंचते हैं,तो उन्हें सीधे निजी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दिया जाता है,वहीं ऑपरेटर द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

शुल्क नहीं दिया तो महीनों का इंतजार- कई किसानों का आरोप है कि यदि वे ऑपरेटर द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर देते हैं,तो उनका काम लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें एक छोटे से दस्तावेज के लिए भी महीनों तक पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं,इस वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।

वसूली का माध्यम बने ऑपरेटर?- स्थानीय लोगों का आरोप है

कि कई पटवारी कार्यालयों में निजी कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक तरह से वसूली का माध्यम बना दिया गया है,ग्रामीणों का कहना है कि बिना पैसे दिए फाइलें आगे नहीं बढ़तीं और किसानों को बार-बार यह कहकर लौटा दिया जाता है कि 'अभी सिस्टम में काम बाकी है' या 'कल आना। कुछ किसानों का यह भी कहना है कि यदि ऑपरेटर के माध्यम से काम कराया जाए तो वही काम जल्दी हो जाता है।

व्यवस्था पर उठे सवाल- इस पूरे मामले ने राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि पटवारी कार्यालयों में निजी ऑपरेटर बैठाए जा रहे हैं, तो यह व्यवस्था किस नियम के तहत चल रही है? लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में बैठकर निजी व्यक्ति द्वारा किसानों से पैसे लेना राजस्व प्रणाली की साख पर भी सवाल खड़ा करता है।

जांच की मांग- मामले को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पटवारी कार्यालयों में निजी कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका की जांच कराई जाए,उनका कहना है कि यदि अवैध वसूली की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

अब प्रशासन के कदम का इंतजार- अब देखना होगा कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और किसानों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि यह मामला केवल अवैध वसूली का नहीं,बल्कि किसानों के अधिकार और राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है।

CMYK

सोनहत में जमीन विवाद

पीड़ित महिला भटकती रही,तहसील में चलता रहा 'समझौते का न्याय'

जमीन गई,न्याय भी गया!

तहसील में मिला सिर्फ एक ही नुस्खा- 'कोर्ट जाइए'

जमीन हड़पने की कहानी : मालिक ही गायब

यह पूरा मामला लगभग 2.93 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है, जो पीढ़ियों से परिवार के नाम पर चली आ रही थी, लेकिन अचानक एक दिन कागज़ों में ऐसा खेल हुआ कि असली हकदार का नाम गायब हो गया और जमीन किसी और के नाम दर्ज हो गई, इतना ही नहीं,जमीन का सौदा भी कर दिया गया,अब सवाल यह है कि अगर जमीन किसी और की थी तो नामांतरण किस आधार पर हुआ? और अगर नामांतरण गलत हुआ तो उसे रोका क्यों नहीं गया? इन सवालों का जवाब अभी तक फाइलों में ही घूम रहा है।

जमीन की कहानीः पीढ़ियों से चली आ रही विरासत

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन मूल रूप से नान्हू सिंह पुत्र माटोराम के नाम दर्ज थी, नान्हू सिंह की मृत्यु के बाद जमीन का फौती नामांतरण उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज हुआ, रिकॉर्ड के अनुसार परिवार की वंशावली इस प्रकार बताई जाती है, नान्हू सिंह पत्नी मानकुंवर,पुत्र बुद्ध,पुत्र सोमारसाय समय के साथ परिवार की कई पीढ़ियां गुजर गई,सोमारसाय की संतानों में बसंती और शांति का नाम सामने आता है,शांति की पुत्री सजनी और उसकी पुत्री नेहा कुमारी बताई जाती है। इसी रिश्ते के आधार पर आगे चलकर जमीन के नामांतरण और स्वामित्व को लेकर विवाद शुरू हुआ।

आरोपःकागजों में बदल गई जमीन की किस्मत

आवेदिका बसंती का आरोप है कि जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा किया गया, शिकायत में कहा गया है कि नेहा कुमारी उसका पति बिजेंद्र कुमार और कथित बिचौलिया बैंकट गुप्ता ने मिलकर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कराया,आवेदिका का आरोप है कि राजस्व दस्तावेजों में उसका नाम जानबूझकर छिपाया गया और बाद में जमीन का नामांतरण नेहा कुमारी के नाम कर दिया गया, इसके बाद कथित रूप से जमीन को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई,भारत में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों में अक्सर जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराएं लगाई जाती हैं,जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468 और 471 शामिल हैं। इन धाराओं में फर्जी दस्तावेज तैयार करना और धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पना गंभीर अपराध माना जाता है।

शपथ पत्र में कबूलनामा?

मामले में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज 23 दिसंबर 2024 का शपथ पत्र है, जिसमें नेहा कुमारी ने कई महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की हैं, शपथ पत्र के अनुसार बसंती जीवित है और जमीन में उसका भी अधिकार हो सकता है, आवेदन और शपथ पत्र में बसंती का नाम दर्ज नहीं कराया गया, बाद में जमीन उसके नाम दर्ज हो गई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथ पत्र में यह भी लिखा गया है कि यदि बसंती चाहे तो वह जमीन की बिक्री राशि का आधा हिस्सा देने को तैयार है, यह स्वीकारोक्ति पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना देती है।

8 लाख 50 हजार में जमीन का सौदा

दस्तावेज़ों में उल्लेख है कि जमीन का सौदा लगभग 8 लाख 50 हजार रुपये में किया गया, बताया गया कि जमीन को,उदित नारायण,डाकेश्वर नारायण नामक व्यक्तियों को बेचा गया,हालांकि शपथ पत्र में यह भी लिखा गया है कि बिक्री के बाद भी नेहा कुमारी को अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है और कथित तौर पर कहा गया है कि बाद में भुगतान किया जाएगा।

-राजन पाण्डेय-
सोनहत (कोरिया),15 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कहते हैं कि तहसील न्याय का पहला दरवाजा होती है, लेकिन सोनहत तहसील में एक महिला के मामले में ऐसा लगता है कि यह दरवाजा न्याय से ज्यादा सलाह केंद्र बन गया है,जहाँ समाधान कम और कोर्ट जाइए का रास्ता ज्यादा बताया जाता है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व तंत्र,जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, आरोप है कि एक गरीब ग्रामीण महिला की पुश्तैनी जमीन को पहले राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी तरीके से नामांतरण कराया गया और बाद में उसे बेचने की तैयारी भी कर ली गई,दस्तावेज़ों और शिकायत पत्रों से सामने आई जानकारी बताती है कि यह पूरा मामला खसरा नंबर 62, 73 और 201 की लगभग 2.93 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है,इस जमीन को लेकर आवेदिका बसंती ने प्रशासन और पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया,यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी आईना है,जिसमें गरीब और कम पढ़े-लिखे ग्रामीणों की जमीन अक्सर कागजों के खेल में गायब हो जाती है। ग्राम बिरौरीडांड़ की एक महिला की पुश्तैनी जमीन पहले कागज़ों में गायब हुई,फिर किसी और के नाम चढ़ गई और आखिर में बेच भी दी गई और जब महिला न्याय की उम्मीद लेकर तहसील पहुंची तो उसे जमीन वापस दिलाने की जगह समझौते का फार्मूला सुझाया गया,मामले के केंद्र में हैं सोनहत के तहसीलदार संजय राठौर,जिनकी कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है,सोनहत की इस कहानी में जमीन भी है, कागज़ भी हैं और कानून भी है,बस जो नहीं दिख रहा वह है– न्याय, एक ओर महिला अपनी जमीन के लिए दर-दर भटक रही है और दूसरी ओर प्रशासनिक फाइलें अपनी गति से चल रही हैं,अब देखना यह है कि यह मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों की धूल में दब जाएगा या सच में किसी दिन न्याय की रोशनी देखेगा।

सवाल जो जवाब मांगते हैं..

- जमीन का नामांतरण किन परिस्थितियों में हुआ?
- क्या सभी वारिसों की जानकारी ली गई थी?
- क्या राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ?
- क्या प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की? और सबसे बड़ा सवाल- क्या तहसील का काम न्याय देना है या लोगों को कोर्ट भेजना?

घटती घटना
कोरिया-सूरजपुर-समाचार
अम्बिकापुर,सोमवार 02 जून 2025
5
तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप का क्या कलेक्टर सूरजपुर उन्हें तहसील कार्यालय से पृथक कर जांच करवाएंगे?
सूरजपुर में कलयुग का कपूत
विवादों से है इनका का गहरा नाता

प्रशासन के सामने शिकायतों की लंबी सूची

बसंती ने इस मामले में कई अधिकारियों को शिकायत भेजी है,जिनमें शामिल हैं,कलेक्टर कोरिया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनहत, तहसीलदार सोनहत,थाना प्रभारी सोनहत,पुलिस अधीक्षक कोरिया,आईजी सरगुजा रेंज शिकायत में कहा गया है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जमीन पूरी तरह बेच दी जाएगी और उसे न्याय नहीं मिल पाएगा।

तहसील में न्याय नहीं,समझौते का प्रस्ताव

पीड़ित महिला जब तहसील कार्यालय पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि तहसीलदार मामले की जांच करेंगे और अगर जमीन गलत तरीके से किसी और के नाम दर्ज हुई है तो उसे रोका जाएगा,लेकिन यहां कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया, शिकायतकर्ता के अनुसार तहसीलदार ने कहा कि जमीन खरीदने वाले पक्ष से बात करके पैसे दिलवा दिए जाएंगे, यानी जमीन गई तो गई,कम से कम पैसे मिल जाएं,यह सुनकर ऐसा लगा मानो तहसील न्यायालय नहीं बल्कि जमीन सौदे का मध्यस्थ कार्यालय हो।

जब पैसे लेने पहुंची तो जवाब मिला

पैसे नहीं देंगे लेकिन असली नाटक तब हुआ जब महिला पैसे लेने के लिए जमीन खरीदने वाले लोगों के पास पहुंची, जवाब साफ था पैसे नहीं देंगे,अब सवाल यह उठता है कि जब पैसे देने से ही इनकार था तो तहसीलदार ने समझौते की सलाह किस भरोसे पर दी थी?

हम क्या कर सकते हैं,कोर्ट जाइए...

जब महिला दोबारा तहसील पहुंची तो उसे बताया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तहसीलदार का कथित जवाब था, अब नामांतरण हो चुका है, रजिस्ट्री भी हो गई है,अगर निरस्त कराना है तो सिविल कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते,यह सुनकर ग्रामीणों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है,अगर तहसील कुछ नहीं कर सकती तो फिर तहसील है किसलिए?

नियमों की नई व्याख्या

मामले में एक और दिलचस्प तर्क सामने आया,कहा गया कि रजिस्ट्री होने के बाद ऑनलाइन नामांतरण करना मजबूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय यह रजिस्ट्री हुई थी उस समय यह नियम लागू ही नहीं था, अब सवाल यह है कि जब नियम बाद में आया तो नामांतरण किस नियम के तहत किया गया? या फिर नियम भी परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं?

तहसीलदार संजय राठौर फिर सुर्खियों में...

सोनहत के तहसीलदार संजय राठौर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं, जब वे सूरजपुर जिले में पदस्थ थे तब भी जमीन से जुड़े विवादों में उनका नाम सामने आया था,अब सोनहत में भी जमीन विवाद के इस मामले ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है,स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी कार्यशैली ऐसी है कि हर मामला आखिर में कोर्ट की ओर भेज दिया जाता है, यानी तहसील का रास्ता अक्सर अदालत की सीढ़ियों पर खत्म होता है।

गरीब के लिए न्याय सबसे महंगा

कानून कहता है कि हर नागरिक को न्याय का अधिकार है, लेकिन जमीन विवाद में अदालत जाना किसी गरीब ग्रामीण के लिए आसान नहीं होता, सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाना,लंबी प्रक्रिया,भारी खर्च,वर्षों का इंतजार इन सबके बीच अक्सर गरीब व्यक्ति हार मान लेता है, शायद यही वजह है कि जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों में गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं।

न्यायालय में सुरक्षा की चर्चा

स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसीलदार की कार्यशैली ऐसी है कि वे अपने न्यायालय में हमेशा सुरक्षा में रहते हैं, गांव में चर्चा है कि निर्दोषों को न्याय दिलाने के बजाय ऐसे मामलों में अक्सर वही लोग मजबूत दिखते हैं जिनकी जेब मजबूत होती है,लेकिन जमीन विवाद के इस मामले ने इन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है।

जमीन से बड़ा कोई सवाल नहीं...

ग्रामीण भारत में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि जीवन का आधार होती है, जब वही जमीन कागज़ों में गायब हो जाए तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का बन जाता है, सोनहत की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गरीब आदमी की जमीन सच में सुरक्षित है? या फिर वह सिर्फ फाइलों और रजिस्टरों की दया पर टिकी हुई है।

कागजों का खेल या साजिश?

कोरिया जिले का यह मामला बताता है कि जमीन का विवाद केवल परिवारों के बीच नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरियों से भी पैदा होता है, एक ओर गरीब महिला न्याय के लिए दर-दर भटक रही है,दूसरी ओर दस्तावेज़ों में जमीन का मालिक बदल चुका है,अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को साधारण विवाद मानकर टाल देता है या फिर जमीन जालसाजी के इस पूरे नेटवर्क की जांच करता है।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नई मजबूतीः एमसीबी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

हसदेव इन होटल में गरिमामय समारोह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित न्यायपालिका व जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित

-संवाददाता-
एमसीबी,15 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जिले में एमसीबी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शहर के हसदेव इन होटल में गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारी पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में न्यायाधीश राजेन्द्र वर्मा, न्यायाधीश विवेक तिवारी,न्यायाधीश लोकेश कुमार,नगर निगम के महापौर राम नरेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव,उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा,जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे,कमांडेंट संजय शर्मा,अतिरिक्त लोक अभियोजक गोपाल सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल,ग्रीन वैली संस्थान के प्रतिनिधि सहित जिले के कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहले निर्वाचित पदाधिकारियों और उसके बाद मनोनीत पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश लोकेश कुमार ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता का कार्य केवल समाचार देना ही नहीं बल्कि सरकार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। यदि पत्रकार निष्पक्षता और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाएं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने कहा कि पत्रकारों की कलम में समाज को सही दिशा देने की शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता अत्यंत जिम्मेदारी का कार्य है और बिना किसी ठोस आधार के खबर प्रकाशित होने से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पत्रकारों को सत्य, संतुलन और निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ी अंदाज में पत्रकारों की भूमिका और मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि पत्रकार हर स्थान से खबरें जुटाकर समाज तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी दिन अखबार नहीं आता तो समाज में एक प्रकार का खालीपन महसूस होता है,जिससे पत्रकारिता के महत्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं वाला लोकतांत्रिक देश है,जहां न्यायपालिका और प्रेस दोनों ही स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जनता का विश्वास बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे निष्पक्षता के साथ समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार रत्न जैन को उनके लंबे समय से किए जा रहे पत्रकारिता के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया।

तहसील साहू संघ भैयाथान की कार्यकारिणी घोषित

नीरज साहू बने मीडिया प्रभारी,प्रवीण साहू को मिली सह-मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी

-संवाददाता-
सूरजपुर/भैयाथान,15 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

साहू समाज की सामाजिक गतिविधियों के प्रभावी प्रचार-प्रसार और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तहसील साहू संघ भैयाथान की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है,जिला अध्यक्ष रामलल्लू साहू की सहमति तथा तहसील अध्यक्ष सौरभ साहू की अनुशंसा पर दो सक्रिय पत्रकारों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी जानकारी के अनुसार डबरीपारा निवासी नीरज साहू,जो एक दैनिक समाचार-पत्र के जिला प्रतिनिधि हैं,को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है,वहीं बांसापारा निवासी प्रवीण साहू,जो एक दैनिक समाचार-पत्र के जिला प्रतिनिधि हैं,को सह-मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। समाज की गतिविधियों को मिलेगा नया मंच- नवनियुक्त मीडिया प्रभारी नीरज साहू ने कहा कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे, उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि समाज की सभी गतिविधियों, कार्यक्रमों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सह-मीडिया प्रभारी प्रवीण साहू ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और सोशल मीडिया का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में समाज की उपलब्धियों और सकारात्मक कार्यों को व्यापक मंच देना बेहद आवश्यक है, नई जिम्मेदारी मिलने पर जिला अध्यक्ष रामलल्लू साहू, तहसील अध्यक्ष सौरभ साहू सहित साहू समाज के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने दोनों नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2 रामानुजगंज

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.costate.gov.in

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 30.03.2026 (1730 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है -

सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी. एस.टी. छोड़ कर (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
185958	10/व.ले.लि/2025-26 दिनांक 11.03.2026	रामनगर जलाशय योजना का नवीनीकरण कार्य ।	246.83	द्वितीय आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov पर दिनांक 18.03.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट 1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस. ओ. आर. दिनांक 01.08.2010 (संशोधित 22.08.2022) के अनुसार है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 2. रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
कृते मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी नंबर-252607163/5

CMYK

कोरिया में विकास की गंगा या रिकॉर्ड की राजनीति

चमकदार उपलब्धियों के बीच बुनियादी सवाल खड़े

?

गोल्डन बुक में नाम,लेकिन सड़क अब भी तंग—यही है विकास मॉडल,रिकॉर्ड में चमका कोरिया,जमीन पर विकास अब भी खोज में...

जिले में 19 कलेक्टर,हर कार्यकाल में विकास की अपनी कहानी,रिकॉर्ड,मॉडल और पर्यटन की चमक के बीच बुनियादी जरूरतें अब भी प्रतीक्षा में...

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद सामने आई प्रशासनिक अव्यवस्था,सड़क चौड़ीकरण जैसे जरूरी विकास पर अब भी उम्मीदें अधूरी...

जब विकास की तस्वीर ही धराशाई हो गई...

स्थिति उस समय और अजीब हो गई जब एक विकास कार्य की तस्वीर ही जमीन पर धराशाई हो गई, जिस विकास को प्रशासन अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहा था वही अचानक विवाद का कारण बन गया, मामले में एक अधिकारी पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन इससे प्रशासन की छवि में सुधार की बजाय यह चर्चा अधिक होने लगी कि कहीं न कहीं जल्दबाजी और दिखावे की प्रवृत्ति भी विकास की गति को प्रभावित कर रही है।

जिले को जिस विकास की जरूरत,वही सूची से बाहर

कोरिया जिले में विकास की चर्चा लगातार हो रही है,लेकिन जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के लोगों के मन में एक सवाल बार-बार उठता है, शहर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण आखिर कब होगा? यह सिर्फ यातायात का मुद्दा नहीं बल्कि शहर की भविष्य की जरूरत है, लेकिन यह विषय अब तक विकास की प्राथमिक सूची में प्रमुखता से दिखाई नहीं देता।

सूरजपुर की याद क्यों आती है...

जिला मुख्यालय के लोग अक्सर सूरजपुर के एक पूर्व कलेक्टर को याद करते हैं जिन्होंने सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया था,विरोध हुआ,आलोचना हुई,लेकिन उन्होंने शहर की संरचना बदलने का जोखिम उठाया,लोगों का मानना है कि उस निर्णय में व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा शहर के भविष्य की चिंता थी।

रिकॉर्ड की दौड़ और सोखता गड्ढों की कहानी

वर्तमान कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस उपलब्धि की हुई वह थी एक दिन में बड़ी संख्या में सोखता गड्ढों का निर्माण,जिसके कारण जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ,यह उपलब्धि निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी मानी गई। लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा भी चली कि यदि इसी ऊर्जा और संसाधन का उपयोग बुनियादी ढांचे में होता तो उसका प्रभाव और व्यापक दिखाई देता, व्यंग्य में कई लोग यह भी कहते नजर आए कि कोरिया में अब विकास की माप सड़क से नहीं, रिकॉर्ड से होने लगी है।

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी जिले के विकास की कहानी अक्सर दो तरह की सोच के बीच चलती दिखाई देती है, पहली सोच वह होती है जिसमें प्रशासन का लक्ष्य जिले और जनता का वास्तविक विकास होता है, दूसरी सोच वह होती है जिसमें विकास के नाम पर कई चमकदार तस्वीरें जरूर बनती हैं,लेकिन उनके पीछे कभी-कभी व्यक्तिगत ख्याति,प्रशंसा और पदोन्नति की संभावनाएं भी झलकने लगती हैं।

जब कोई कलेक्टर किसी जिले में पदस्थ होता है और उसके कार्यकाल में लगातार विकास की खबरें सामने आती हैं तो यह स्वाभाविक है कि जनता उम्मीद करती है कि यह विकास जमीन पर भी उतना ही दिखाई देगा जितना रिपोर्टों और प्रस्तुतियों में दिखता है,कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ मामलों में विकास की तस्वीरें इतनी चमकदार बन जाती हैं कि वास्तविकता की परछाई पीछे छूट जाती है, किसी भी जिले में जब कोई कलेक्टर पदस्थ होता है तो उसके कार्यकाल को लेकर आमतौर पर दो तरह की अवधारणाएं सामने आती हैं,पहली यह कि वह जिले के समग्र विकास के लिए नई सोच और योजनाओं के साथ काम कर रहा है,दूसरी यह कि कहीं विकास के नाम पर दिखाई जा रही गतिविधियां व्यक्तिगत ख्याति, प्रशंसा और पदोन्नति की सीढ़ी तो नहीं बन रही हैं, दरअसल किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल को लेकर यही दो तस्वीरें अक्सर चर्चा में रहती हैं,एक जमीनी विकास की,और दूसरी दिखाए जा रहे विकास की, कई बार दोनों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि फर्क समझना मुश्किल हो जाता है,और कई बार यह दूरी इतनी ज्यादा होती है कि सवाल अपने आप खड़े होने लगते हैं।

5 प्रतिशत मॉडल और किसानों की उलझन

इसके बाद जिले में 5 प्रतिशत मॉडल की चर्चा तेज हुई,किसानों से अपील की गई कि वे अपनी कृषि भूमि का पांच प्रतिशत हिस्सा जल संरक्षण के लिए छोड़ दें,कुछ किसानों ने इसे अपनाया भी,लेकिन कई ग्रामीणों में यह भ्रम फैल गया कि कहीं उनकी जमीन का यह हिस्सा शासकीय नियंत्रण में न चला जाए, योजना का उद्देश्य सकारात्मक था,लेकिन इसकी जानकारी और विश्वास की कमी ने इसे अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ने दिया।

झुमका पर्यटन स्थल की चमक फीकी

कोरिया जिले के पर्यटन की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया झुमका क्षेत्र भी चर्चा में रहा, यहां वोट क्लब और अन्य सुविधाओं को विकसित कर इसे पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री ने भी यहां बोटिंग की,जिससे यह स्थान चर्चा में आया,लेकिन अगले ही दिन जब पर्यटक पहुंचे तो उन्हें अंधेरा,अधूरी व्यवस्था और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा,सोशल मीडिया पर पर्यटकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि अव्यवस्था देखने के लिए पार्किंग शुल्क देना उन्हें मंजूर नहीं।

ओपन थिएटर की उपलब्धि भी सवालों में

झुमका क्षेत्र में बनाए गए ओपन थिएटर को एक नई उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया था,लेकिन जब आसपास की सुविधाएं ही अधूरी दिखाई दीं तो यह उपलब्धि भी आलोचना का कारण बन गई, जिस स्थल को कोरिया जिले के पर्यटन का गौरव बताया जा रहा था,वहीं की अव्यवस्थाओं ने प्रशासन की छवि पर सवाल खड़े कर दिए।

विकास की असली पहचान क्या है...

कोरिया जिले में विकास की बातें आज भी जारी हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं,मॉडल तैयार हो रहे हैं और योजनाओं की घोषणाएं भी हो रही हैं,लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल गहराता जा रहा है, क्या विकास का मतलब रिकॉर्ड बनाना है या वह बदलाव जो आम लोगों की जिंदगी को आसान बना दे? क्योंकि इतिहास में वही विकास याद रखा जाता है जो लोगों के जीवन में दिखाई देता है,न कि वह जो केवल रिपोर्टों और प्रस्तुतियों में चमकता है।

19 कलेक्टर और विकास की परंपरा

कोरिया जिले की बात करें तो यहां अब तक 19 कलेक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं,यह भी सच है कि जिले का विकास कभी पूरी तरह रुका नहीं,हर कलेक्टर अपने साथ कुछ नए विचार, कुछ नए प्रयोग और कुछ प्रशासनिक पहल लेकर आया,किसी ने शिक्षा पर ध्यान दिया,किसी ने सड़क और भवन निर्माण को प्राथमिकता दी, तो किसी ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की,कई कलेक्टरों के कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि उनके निर्णयों का असर सीधे जनता के जीवन में दिखाई देता था,लेकिन समय के साथ विकास की परिभाषा भी बदलती दिखाई दी, अब कई बार विकास का मतलब रिकॉर्ड,मॉडल और प्रस्तुतियों की चमक से भी जोड़ा जाने लगा।

वर्तमान कार्यकाल और विकास की चमकदार तस्वीरें

वर्तमान कलेक्टर के कार्यकाल में भी जिले में विकास की कई तस्वीरें सामने आई हैं,प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि जिले में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसा माहौल बनाया गया है मानो जिले में विकास की गंगा-जमुना बह रही हो,लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इन तस्वीरों में पूरी सच्चाई भी मौजूद है या फिर कुछ तस्वीरें केवल प्रस्तुति की कला का हिस्सा बनकर रह गई हैं।

मुख्यमंत्री का दौरा और प्रशासनिक समन्वय की परीक्षा

हाल ही में मुख्यमंत्री का दो दिवसीय प्रवास कोरिया जिले में हुआ,किसी भी जिले में मुख्यमंत्री का दौरा प्रशासनिक क्षमता और समन्वय की परीक्षा माना जाता है, लेकिन इस दौरे के दौरान और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए, देर रात विश्रामगृह से शुरू हुई अव्यवस्था की चर्चा धीरे-धीरे पूरे प्रशासनिक ढांचे तक पहुंच गई, कहीं ठहराव को लेकर विवाद हुआ,कहीं जनप्रतिनिधियों ने सम्मान को लेकर नाराजगी जताई,इन घटनाओं ने यह संकेत जरूर दिया कि विकास की चमकदार तस्वीरों के पीछे प्रशासनिक समन्वय की तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिख रही।

कोरिया जिले में इस समय कुछ सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं...

क्या जिले में दिखाया जा रहा विकास दीर्घकालिक है?

क्या यह योजनाएं आने वाले वर्षों में भी जारी रहेंगी?

या फिर यह सब केवल एक प्रशासनिक कार्यकाल की उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि कई बार विकास के नाम पर किए गए प्रयोग जिले से ज्यादा अधिकारियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में दर्ज हो जाते हैं।

अंत में...

कोरिया जिले का विकास होना बेहद जरूरी है और यह स्वागत योग्य भी है, लेकिन विकास की असली पहचान वही होती है जो जमीन पर दिखाई दे और लंबे समय तक टिके,अगर विकास की तस्वीरें केवल प्रस्तुतियों,कार्यक्रमों और रिपोर्टों तक सीमित रह जाएं तो वह विकास नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन बनकर रह जाता है,अब देखना यह है कि कोरिया जिले में दिखाई जा रही विकास की यह चमक वास्तविक परिवर्तन की कहानी बनेगी, या फिर यह केवल प्रशासनिक उपलब्धियों की सूची में दर्ज एक और अध्याय बनकर रह जाएगी,क्योंकि अंततः जनता की नजर में वही विकास सच्चा होता है जो दिखे भी और टिके भी।

बिना समुचित तैयारी के कर दिया गया बस स्टैंड का स्थानांतरण,यात्रियों के बैठने के लिए न शेड,न बेंच,पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव

बड़ा बाजार से हटाया गया पुराना बस स्टैंड,नए स्थान पर यात्रियों के लिए नहीं कोई सुविधा

-संवाददाता-

एमसीबी/चिरमिरी,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

चिरमिरी शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में वर्षों से संचालित हो रहा पुराना बस स्टैंड हाल ही में हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है,प्रशासन द्वारा किए गए इस स्थानांतरण के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नए स्थान पर यात्रियों के लिए बेहतर और व्यवस्थित बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। नए स्थान पर बसों का संचालन तो शुरू हो गया है,लेकिन यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है,न तो वहां बैठने के लिए शेड है और न ही यात्रियों के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पेयजल,शौचालय और साफ-सफाई जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है,इससे रोजाना बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

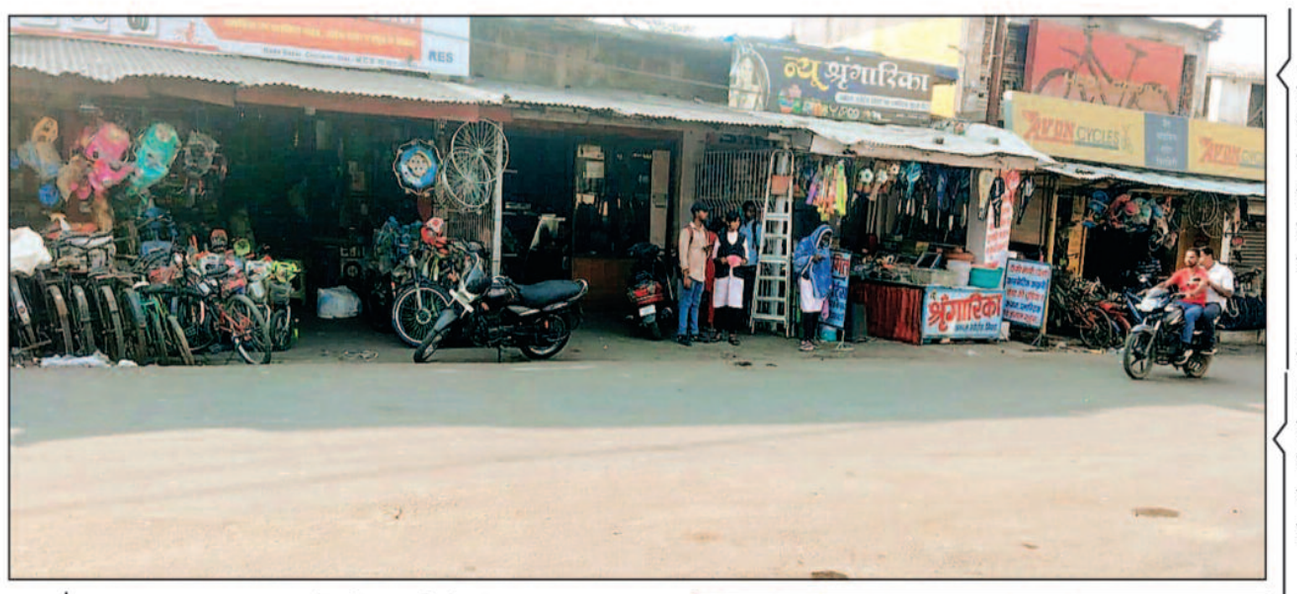

जल्दबाजी में किया गया स्थानांतरण

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का निर्णय शायद जल्दबाजी में लिया गया है,पुराने बस स्टैंड को तो हटा दिया गया,लेकिन नए स्थान को बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की दिशा में कोई ठोस तैयारी दिखाई नहीं देती,लोगों का कहना है कि यदि पहले से योजना बनाकर नए स्थान पर आवश्यक सुविधाएं विकसित की जातीं तो यात्रियों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।

धूप और गर्मी में खड़े रहने को मजबूर यात्री

नए बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए न तो कोई बेंच लगाई गई है और न ही छाया के लिए शेड का निर्माण किया गया है,ऐसे में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है,दिन के समय तेज धूप और गर्मी में यह स्थिति और भी अधिक कष्टदायक हो जाती है,कई बार बसों के देरी से आने पर यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है,जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी

बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सबसे अधिक असर बुजुर्गों,महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है,बुजुर्ग यात्रियों को लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल हो जाता है,जबकि महिलाओं और बच्चों को भी धूप और गर्मी में इंतजार करना पड़ता है,कई यात्रियों ने बताया कि यदि बैठने और छाया की व्यवस्था होती तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती थी।

पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं का भी अभाव

नए बस स्टैंड पर पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यात्रियों को पीने के पानी के लिए आसपास की दुकानों या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है,इसके अलावा शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है,जिससे विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है,बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगह पर इन बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े करता है।

सिर्फ स्थानांतरण,व्यवस्था नहीं...

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन ने बस स्टैंड को तो हटा दिया, लेकिन नए स्थान को व्यवस्थित बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए,लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो केवल औपचारिक रूप से बस स्टैंड को स्थानांतरित कर दिया गया हो,जबकि यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज कर दिया गया है।

स्थानीय लोगों में बढ़ रहा असंतोष

बस स्टैंड की वर्तमान स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों और यात्रियों में असंतोष भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में बस स्टैंड जैसी महत्वपूर्ण सुविधा को बिना पर्याप्त तैयारी के स्थानांतरित करना उचित नहीं था,कई नागरिकों ने यह भी कहा कि प्रशासन को पहले नए स्थान पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करनी चाहिए थीं और उसके बाद ही बस स्टैंड को स्थानांतरित करना चाहिए था।

प्रशासन से की जा रही है मांग...

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि नए बस स्टैंड पर जल्द से जल्द यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं,लोगों का कहना है कि यहां शेड,बैठने की व्यवस्था,पेयजल,शौचालय और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत विकसित की जानी चाहिए,ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

समस्या जल्द हल नहीं हुई तो बढ़ेगी परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही बस स्टैंड पर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो आने वाले समय में यात्रियों की समस्या और बढ़ सकती है,विशेष रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में बिना शेड और अन्य सुविधाओं के बस का इंतजार करना यात्रियों के लिए और अधिक कठिन हो जाएगा,अब देखना यह है कि प्रशासन यात्रियों की इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेता है और नए बस स्टैंड को सुविधायुक्त बनाने के लिए कब तक ठोस कदम उठाता है।

C M Y K

मेहनती और टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में पहचान बनाई श्रुति हासन ने

मशहूर अभिनेता कमल हासन की बेटी श्रुति कमल हासन की पहचान केवल एक स्टार किड के तौर पर नहीं,बल्कि एक मेहनती और टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में बनी है। 1986 में जन्मीं श्रुति हासन, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन और मशहूर अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बेटी हैं। हासन परिवार में जन्म लेने के बावजूद श्रुति ने अपनी राह खुद बनाई। वह न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक स्थापित गायिका और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। श्रुति ने चेन्नई के एबाकस मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की और दसवीं तक वहीं शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें संगीत और सिनेमा में गहरी रुचि थी। इसी लगाव ने उन्हें आगे चलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया,जहां उन्होंने संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग ली। महज छह साल की उम्र में श्रुति हासन ने अपने पिता की फिल्म थेवर मगन (1992) में पहला गाना गाया, जिसे इलैया राजा ने कंपोज किया था। इसके बाद स्कूल के दिनों में उन्होंने हिंदी फिल्म चाची 420 (1997) में भी गायन किया। साल 2000 में कमल हासन के निर्देशन में बनी फिल्म हे राम में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और उसी फिल्म के लिए हिंदी और तमिल में टाइटल थीम रामा रामा भी गाई। एक अभिनेत्री के तौर पर श्रुति ने वयस्क भूमिका में डेब्यू 2009 में बॉलीवुड फिल्म 'लक' से किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया और यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। श्रुति को असली पहचान तेलुगु फिल्म अनागनगा ओ धीरुडु (2011) से मिली। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। रेस गुर्रम (2014) में दमदार भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु मिला। कुल मिलाकर श्रुति के नाम तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स सहित कई सम्मान दर्ज हैं। हिंदी सिनेमा में श्रुति हासन ने डी-डे, रामैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया। जहां कुछ फिल्मों को समीक्षकों की सराहना मिली, वहीं कुछ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अभिनय के साथ-साथ संगीत श्रुति हासन की पहचान का अहम हिस्सा है। वह एक स्थापित पार्श्व गायिका हैं। साल 2009 में उन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन उन्नैपोल ओरुवन से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का म्यूजिक भी तैयार किया और बैंड के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई।

बहन प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म में लेना अफोर्ड नहीं कर सकती : मीरा चोपड़ा

मीरा चोपड़ा साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन के तौर पर पहचानी जाती हैं। शादी के बाद वह फिल्मों से दूर थीं लेकिन अब बतौर फिल्ममेकर उन्होंने साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' के साथ वापसी की। बतौर फिल्ममेकर डेब्यू करने के बाद क्या वह आगे अपनी फिल्म में बहन प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने के बारे में सोचती हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा, 'नहीं...नहीं। अभी तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं अभी उनको एफोर्ड ही नहीं कर सकती हूं। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचती हूं। हां जब बड़ी फिल्ममेकर बन जाऊंगी तो एक दिन अपनी फिल्म में प्रियंका को कास्ट करना चाहूंगी।'

फिल्म बनाने के लिए प्रियंका ने किया प्रेरित

बिजनेस में हाथ आजमाने के मीरा के फैसले पर बहन प्रियंका चोपड़ा का क्या रिएक्शन था? इस बारे में वह बताती हैं, 'मैंने सीधे उन्हें अपनी फिल्म (गांधी टॉक्स) का टीजर भेजा। मैंने उनको बताया कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। उनको इस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। प्रियंका का व्यवहार कुछ ऐसा है कि हम में से कोई जब कुछ अच्छा करता है, तो वह बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। प्रियंका ने मुझे कहा था कि फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आपने टीजर बना दिया है तो प्लीज अब फिल्म बनाओ। दरअसल,उन्होंने इस इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वो ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। जब आपके परिवार में ऐसा कोई होता है तो आप उससे प्रेरित होते हैं। आप पहले उसको देखते हैं। हमेशा एक चाह थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि प्रियंका कहे कि मुझे तुम पर गर्व है और उन्होंने ऐसा कहा,ये मेरे लिए ये बड़ी है।

एक्टिंग में लगातार काम नहीं मिलता

एक इंटरव्यू में मीरा ने कहा था कि वह स्क्रीन पर वापसी के लिए लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन अब वह बतौर फिल्ममेकर वापसी कर रही हैं। क्या शादी के बाद एक्टिंग में लौटना उनके लिए चुनौती भरा फैसला है? इस पर वह कहती हैं, 'मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन एक्टिंग में क्या है कि आपको दो साल काम नहीं मिला तो आप काम नहीं करोगे,फिर एकदम से एक ही साल में दो प्रोजेक्ट आ जाएं तो आप काम करोगे। दरअसल,एक्टिंग ऐसा पेशा नहीं है कि लगातार आपको काम दे ही देगा। मैं ऐसा प्रोफेशन चाहती थी कि आपका लगातार काम चलता रहे, इसलिए मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कब क्या बनाना है, क्या करना है। एक्टिंग में तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तब आप कर पाओगे। मैंने तीन साल काम करने के बाद फिर सोचा कि अब एक्टिंग में वापसी करूंगी।

फिल्म के गाने बनाने में समय लग गया

साइलेंट फिल्म के साथ बतौर प्रोड्यूसर वापसी करना और फिल्म की स्क्रीनिंग के लंबे समय बाद रिलीज करना कितनी बड़ी चुनौती थी? इस बारे में वह कहती हैं,'जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो हमारा मकसद था कि इतना बड़ा स्टेप उठाने पर लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा, जो कि काफी अच्छा था। फिर हमने एक बड़ा बदलाव किया कि फिल्म का संगीत पांच भाषाओं में बनाएंगे, क्योंकि फिल्म में डायलॉग नहीं थे तो फिल्म को एक भाषा में रिलीज करना हमें सही नहीं लगा। इसलिए ए.आर रहमान सर ने शुरू से फिल्म का संगीत बनाना शुरू किया। हिंदी के गाने पहले से ही तैयार थे,तमिल,मलयालम,तेलुगु,मराठी के गाने बनाने शुरू किए। उसमें एक साल और लग गया। लेकिन हमारी मंशा थी कि चाहे एक-दो साल लग जाएं लेकिन जब फिल्म दर्शकों के सामने आए तो लोगों की वाहवाही मिले।

दिल्ली के बारे में कोई बुराई करें तो सहन नहीं होता'

मीरा दिल्ली से हैं। दिल्ली के बारे में वह किन चीजों को याद करती हैं? वह कहती हैं,'मैं दिल्ली आकर मोती महल का बटर चिकन जरूर खाती हूं। मेरा भाई कहीं से बिरयानी लेकर आता है। मैं मॉडल टाउन में रहती हूं तो वहां पर छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद हैं। मुंबई में मैं इतने सालों से रह रही हूं लेकिन दिल्ली का जो खाना है,वो वहां मिलता ही नहीं है। दिल्ली का स्ट्रीट फूड कमाल का है,गोलगप्पे टेस्टी होते हैं। मैं जब भी आती हूं तो हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करती ही हूं। कोई अगर दिल्ली की बुराई करता है तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता। मैं हमेशा दिल्ली के बारे में अच्छी बात सुनना चाहती हूं। (हंसते हुए) अगर मुझे मुंबई में कोई ये कहता है कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है तो मैं ये भी पूछती हूं कि मुंबई में कितना है?

मेरी निजी जिंदगी के मुद्दों को लेकर चिंता न करें : थलापति विजय

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अफवाहें चल रही है कि 27 साल की शादी के बाद उनका पत्नी संगीता सोर्नालिंगम से तलाक हो सकता है। इन खबरों के बाद सोशल मीडिया और फिल्म जगत में उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब इन अटकलों के बीच विजय ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में अभिनेता एक महिला सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। विजय ने कहा कि उनके आसपास चल रही परेशानियों को लेकर लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं और वह खुद ही इनका समाधान निकाल लेंगे। विजय ने अपने प्रशंसकों से अपील करते हुए कहा कि वे इन बातों को

लेकर परेशान न हों। अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब होता है,जब वह देखते हैं कि उनके कारण उनके चाहने वाले तनाव में आ जाते हैं। विजय ने कहा कि उनके प्रशंसकों का समर्थन और प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है और वह नहीं चाहते कि उनकी निजी जिंदगी की वजह से कोई भी परेशान हो। गौरतलब है कि इन दिनों विजय का नाम अभिनेत्री त्रशा क्रष्णन के साथ भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दोनों को एक शादी समारोह में साथ देखा गया था,जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई।

मिडलाइफ महिलाएं समझने लगती हैं अपनी वास्तविक कीमत : लिसा रे

सोशल मीडिया के जरिए कनाडाई-भारतीय अभिनेत्री लिसा रे महिलाओं के स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने और जीवन से जुड़े कई अहम विषयों पर खुलकर अपने विचार साझा करती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिडलाइफ को लेकर एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पोस्ट साझा किया,जिसमें उन्होंने इस दौर को महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण और सशक्त चरण बताया। लिसा रे ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, तब महिलाओं के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार इस समय लोग दूसरों को खुश करने की पुरानी आदतों से बाहर निकलने लगते हैं और खुद पर संदेह करना भी धीरे-

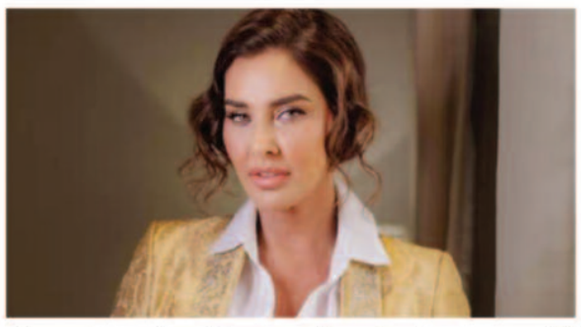

धीरे कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में मानसिक शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगने लगती है और व्यक्ति अपने लिए तय की गई सीमाओं और नियमों को ज्यादा मजबूती से स्वीकार करता है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि मिडलाइफ केवल शारीरिक बदलावों का दौर नहीं है, बल्कि यह वह समय भी होता है जब जीवन से कई अनावश्यक चीजें अपने-आप दूर होने लगती हैं। इस दौरान व्यक्ति कम माफी मांगता है और खुद को बार-बार साबित करने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। उन्होंने लिखा कि इस उम्र में महिलाएं अपनी वास्तविक कीमत समझने लगती हैं और जरूरत पड़ने पर स्पष्ट रूप से 'ना' कहना भी सीख जाती हैं। इससे जीवन अधिक संतुलित और सुकूनभरा हो जाता है। अपनी बात को समाप्त करते हुए लिसा रे ने कहा कि मिडलाइफ को किसी संकट या परेशानी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक यह वह खास समय है जब एक महिला अपनी असली ताकत के साथ जीना शुरू करती है। यह जीवन की कहानी का दूसरा अध्याय होता है,जो पूरी तरह उसका अपना होता है और जिसमें वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती है। बताया जाता है कि लिसा रे 1990 के दशक की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल रही हैं। उन्होंने 1994 में फिल्म हंसते खेलते से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म कसूर से मिली।

वेब सीरीज संकल्प में नजर आएंगी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल

छोटे परदे की अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं। जल्द ही अभिनेत्री आगामी वेब सीरीज संकल्प में नजर आएंगी। इस सीरीज में वे अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब की पत्नी माधुरी के किरदार में हैं। रूप ने अपने को-स्टार जीशान के अभिनय की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जीशान बहुत ही शानदार अभिनेता है। एनएसडी से पढ़ाई करने और फिल्मों-वेब सीरीज में इतना अनुभव होने के कारण उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके सीन्स को देखने का नजरिया, भाषा पर अच्छी पकड़ और एनर्जी ने मेरे साथ के सीन को बेहतर बनाया। मैं हर दिन सेट पर उनके आने का इंतजार करती थी। अभिनेत्री ने आगे सीरीज की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि

शानदार कलाकारों के साथ काम करना ही उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उत्साहित कर रहा था। अभिनेत्री ने कहा, जब सबके पास अच्छा काम होता है, तो सेट पर और बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाना पाटेकर सर और प्रकाश सर के साथ काम करना एक्टिंग, फिल्म बनाने और जिंदगी के कई पहलुओं को समझने जैसा था। मेघना मलिक से भी बहुत कुछ सीखा। हम लंच और डिनर के दौरान भी खूब बातें करते थे। वे न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं,बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि सीरीज के लिए उन्हें ऑफर कैसे मिला था। उन्होंने बताया, साल 2019 तक मैंने टेलीविजन से आगे जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था।

खेल समाचार

इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में अल्काराज हारे

मेदवेदेव ने 6-3, 7-6 से हराया,विमेंस सिंगल्स के फाइनल में आर्यना सबालेंका पहुंची

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। कैलिफोर्निया में चल रहे इंडियन वेल्स ओपन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को मेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अल्काराज को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अल्काराज ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम किया था। वहीं, विमेंस सिंगल्स में टॉप सीड आर्यना सबालेंका ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताब के लिए उनका मुकाबला एलिना रायबाकिना से होगा।

मेदवेदेव ने अल्काराज को संभलने का मौका नहीं दिया

मेन्स सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में डेनियल मेदवेदेव और कार्लोस अल्काराज 6-3, 7-6(3) से हराया। रूसी खिलाड़ी ने पहले सेट में शुरुआती ब्रेक लेकर मैच पर नियंत्रण बना लिया और पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में अल्काराज ने वापसी की कोशिश की और खेल को टाई-ब्रेकर तक खींच ले गए। हालांकि,टाई-ब्रेक में मेदवेदेव ने अपने अनुभव

का इस्तेमाल करते हुए 7-6(3) से जीत दर्ज की और फाइनल का टिकट पक्का किया।

जैनिक सिनर से होगा मेदवेदेव का फाइनल मुकाबला : खिताबी मुकाबले में मेदवेदेव के सामने वर्ल्ड नंबर-2 जैनिक सिनर की चुनौती होगी। सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-4 से मात दी। ज्वेरेव एटीपी मास्टर्स-1000 के सभी नौ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले राफेल नडाल,नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे यह उपलब्धि हासिल किया था।

सबालेंका ने लिंडा नोस्कोवा को सीधे सेटों में हराया : विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका का दबदबा देखने को मिला। उन्होंने चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी।

विश्व कप हीरो संजू सैमसन को केरल सरकार करेगी सम्मानित,आज आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम

तिरुवनंतपुरम,15 मार्च 2026। भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को उनके गृह राज्य केरल की सरकार द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा। इसकी पुष्टि केरल सरकार के खेल मंत्रालय ने की है। मंत्रालय के मुताबिक,राज्य सरकार टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और टूर्नामेंट के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे संजू सैमसन को सम्मानित करेगी। सम्मान आज शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार के अन्य मंत्री और विभागों के मुख्य सचिव और गणमान्य अतिथि कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।

टी20 सीरीज : कप्तान अमेलिया केर की तूफानी पारी न्यूजीलैंड ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 80 रन से हराया

नई दिल्ली,15 मार्च 2026। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार को हुई। बे ओवल में खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 80 रन के बड़े अंतर से हराकर सीरीज 1-0 की बढ़त ले ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया प्लिमर ने 44 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 63 और कप्तान अमेलिया केर ने 44 गेंदों पर 2 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 83 गेंदों पर 146 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने ही शून्य पर पहला विकेट गंवा चुकी न्यूजीलैंड के बड़े और सुरक्षित स्कोर की नींव रखी। प्लिमर और केर के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। दक्षिण

अफ्रीका के लिए मासाबाता क्लास और नाडिन डे क्लार्क ने 2-2 विकेट लिए। अयाबोंगा खाका, एन मल्बा को 1-1 विकेट मिला।

191 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड की कसी हुई और घातक गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में 7 विकेट पर 110 रन ही बना सकी और 80 रन से मुकाबला हार गई। तंजिम ब्रिट्स ने सर्वाधिक 29 और कायला रेनेके ने नाबाद 24 रन बनाए। नाडिन डे क्लार्क ने 19 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर ने 2 और सोफी डिवाइन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लिए। 78 रन की पारी खेलने वाली न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मुकाबला 17 मार्च को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

CMYK

शटर बंद...खेल चालू! प्रेम प्रकाश एजेंसी का रहस्य और विभाग की चुप्पी

नकली दवा कांड...बंद हुई प्रेम प्रकाश एजेंसी या बदला ठिकाना? लाइसेंस,निरीक्षण और नियमों पर उठे बड़े सवाल

- नकली दवा कांड : एजेंसी गायब,सिस्टम मौन–किसके संरक्षण में चल रहा कारोबार?
- नकली दवा पर कार्रवाई या खानापूर्ति? भाटापारा कांड में उठे तीखे सवाल
- नाम बदलो,लाइसेंस लो और फिर धंधा शुरू? दवा कारोबार में नया फार्मूला

- नकली दवा से ज्यादा मजबूत 'सेटिंग'? एजेंसी गायब, कार्रवाई भी गायब
- निरीक्षण से पहले खाली दुकान–क्या पहले ही पहुंच गई थी खबर?
- नियमों की उल्टी गंगाः मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट जरूरी, एजेंसी में नहीं
- जनता की सेहत से खेल या सिस्टम की मेहरबानी? नकली दवा कांड में बड़ा सवाल

कार्रवाई के बाद गायब हुई एजेंसी, दूसरे स्थान से कारोबार की चर्चा

निरीक्षण, छुट्टी, सीमित कार्रवाई और नए लाइसेंस की तैयारी–पूरे घटनाक्रम ने खड़े किए कई सवाल

-न्यूज डेस्क-

रायपुर/भाटापारा/बलौदाबाजार,15 मार्च 2026 (घटती-घटना)। नकली दवाओं के मामले में नाम सामने आने के बाद भाटापारा की प्रेम प्रकाश एजेंसी अब कई गंभीर सवालों के केंद्र में आ गई है। औषधि विभाग की कार्रवाई के बाद एजेंसी का पुराना कार्यालय भले ही बंद दिखाई दे रहा हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि दवाओं का कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और यह किसी अन्य स्थान से संचालित किया जा रहा है,यह मामला अब केवल नकली दवाओं की जांच तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि औषधि विभाग की कार्यप्रणाली,निरीक्षण प्रक्रिया,विभागीय कार्रवाई और दवा व्यापार से जुड़े नियमों पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

संत कंवर राम चौक से अचानक बंद हुई एजेंसी

जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश एजेंसी पहले संत कंवर राम चौक,भाटापारा (जिला बलौदाबाजार) में संचालित हो रही थी,लेकिन जैसे ही नकली दवाओं के मामले में इसका नाम सामने आया और विभागीय कार्रवाई शुरू हुई,एजेंसी का शटर बंद हो गया और संचालक कथित तौर पर गायब हो गया, स्थानीय लोगों का कहना है कि एजेंसी के बंद होने के बाद भी दवाओं का कारोबार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

संध्या टिकरिया में नया ठिकाना?

सूत्रों के अनुसार अब यह एजेंसी संध्या टिकरिया क्षेत्र में एक दवा दुकान के पीछे से होलसेल दवाओं का कारोबार कर रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि एजेंसी का नेटवर्क अब भी सक्रिय है,अब सवाल उठता है की क्या औषधि विभाग को इस नए स्थान की जानकारी है? यदि जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि जानकारी नहीं है तो विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

निरीक्षण और विभागीय कार्रवाई पर सवाल

इस पूरे मामले में औषधि निरीक्षक नीरज साहू और औषधि नियंत्रक बेनी राम साहू की भूमिका भी चर्चा में है, बताया जा रहा है कि जब प्रेम प्रकाश एजेंसी की जांच की गई तब औषधि निरीक्षक नीरज साहू अवकाश पर थे, लेकिन इसके बावजूद वे निरीक्षण स्थल पर पहुंचे,इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई,बताया जाता है कि उनके खिलाफ केवल वेतन वृद्धि रोकने जैसी सीमित कार्रवाई की गई,अब सवाल यह उठ रहा है कि इतने गंभीर मामले में इतनी हल्की कार्रवाई क्यों की गई।

रायगढ़ मामले से तुलना

स्थानीय दवा व्यापारियों का कहना है कि इसी तरह का मामला रायगढ़ के सरस्वती मेडिकोज में सामने आया था,वहां जब कार्रवाई पर संदेह हुआ तो विभाग ने दोबारा जांच टीम भेजी और दूसरी जांच में बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद हुई,इसके बाद संबंधित औषधि निरीक्षक और औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया गया,अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि रायगढ़ में इतनी सख्त कार्रवाई हो सकती है तो भाटापारा के मामले में वैसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

संरक्षण के आरोप

सूत्रों का दावा है कि औषधि विभाग के कुछ अधिकारियों के संरक्षण के कारण ही यह एजेंसी अब तक बड़ी कार्रवाई से बची हुई है,कुछ लोगों का आरोप है कि औषधि नियंत्रक बेनी राम साहू के संरक्षण में औषधि निरीक्षक नीरज साहू पर भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

लाइसेंस बदलने की तैयारी?

इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है,सूत्रों के अनुसार पहले इस एजेंसी का लाइसेंस कीर्ति देव सिंघी के नाम पर था,लेकिन अब एजेंसी के लिए किसी नए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस बनवाने की तैयारी की जा रही है,बताया जा रहा है कि यदि नया नाम मिल जाता है तो उसी के नाम पर एजेंसी को फिर से लाइसेंस दिलाने की कोशिश की जा सकती है,यदि ऐसा होता है तो यह सवाल और गंभीर हो जाएगा कि जिस एजेंसी का नाम नकली दवाओं के मामले में सामने आया,वह केवल नाम बदलकर फिर से कारोबार कैसे शुरू कर सकती है।

होलसेल दवा व्यापार के नियमों पर भी सवाल

इस मामले ने दवा व्यापार से जुड़े नियमों पर भी बहस छेड़ दी है,जानकारी के अनुसार होलसेल दवा एजेंसी चलाने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री अनिवार्य नहीं है,कोई भी सामान्य स्नातक (ग्रेजुएट) व्यक्ति होलसेल दवा एजेंसी का लाइसेंस ले सकता है,यहीं से सवाल शुरू होते हैं,क्योंकि यदि कोई व्यक्ति खुदरा मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो वहां फार्मासिस्ट की डिग्री या योग्य फार्मासिस्ट की नियुक्ति अनिवार्य होती है,लेकिन बड़ी मात्रा में दवाओं की आपूर्ति करने वाली होलसेल एजेंसी के लिए ऐसी शर्त अनिवार्य नहीं है।

क्या नियमों में उल्टी गंगा बह रही है?

दवा व्यापार से जुड़े कुछ जानकारों का कहना है कि यह व्यवस्था अपने आप में विरोधाभासी है, जब छोटी दवा दुकान चलाने के लिए तकनीकी योग्यता जरूरी है, तो फिर हजारों-लाखों रुपये की दवाओं का वितरण करने वाली एजेंसी के लिए ऐसी योग्यता अनिवार्य क्यों नहीं है? कुछ लोग व्यंग्य में यह भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दवा व्यापार के नियमों में शायद उल्टी गंगा बह रही है।

जनता की सेहत का सवाल

दवा कारोबार सीधे तौर पर जनता की सेहत से जुड़ा हुआ है, ऐसे में यदि नकली दवाओं का मामला सामने आता है तो उस पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, लेकिन यदि एजेंसी गायब हो जाए, निरीक्षण सवालों में आ जाए और कार्रवाई सीमित रह जाए,तो स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है।

अब निगाहें औषधि विभाग पर

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि औषधि विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है,क्या विभाग प्रेम प्रकाश एजेंसी की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी धीरे-धीरे फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि यह मामला केवल एक एजेंसी का नहीं बल्कि जनता की सेहत, दवा व्यापार की पारदर्शिता और विभागीय विश्वसनीयता का भी है।

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर ओडिशा-छग बॉर्डर में थे सक्रिय

रायपुर,15 मार्च 2026। ओडिशा में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 11 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 63 लाख 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इससे पहले 11 मार्च को बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेसी) से जुड़े 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया था, जिन पर 3 करोड़ 29 लाख रुपये का इनाम था। इसी दौरान ओडिशा में भी 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 1 करोड़ 65 लाख 62 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बताया कि सुरक्षा बलों की टीम लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी रायगढ़ा घुमसार एरिया कमेटी में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। रविवार को भवानीपटना में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी माओवादियों ने अपने हथियार डाले हैं। आत्मसमर्पण के दौरान वे अपने साथ एके-47, इंसास और एसएलआर सहित कुल 11 हथियार भी लेकर आए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लगातार चल रहे ऑपरेशन और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण माओवादी अब मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति में देरी...यूपीएससी ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

रायपुर,15 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मुख्य सचिव को कड़ा पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि अब तक राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है और तत्काल जवाब तलब किया है। यूपीएससी के अवर सचिव दीपक शॉ ने पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आयोग को नहीं भेजी। आयोग ने 13 मई 2025 को योग्य अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था और नियमानुसार पैनल में से किसी एक अधिकारी को तत्काल पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करना था।

आयोग ने पूछा कि 3 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? यदि विलंब हुआ है तो उसका ठोस कारण क्या है।

क्यों फंसा है मामला : सरकार ने यूपीएससी के पैनल के आधार पर अरुण देव गौतम को डीजीपी तो नियुक्त किया, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक का प्रभार देने के बजाय प्रभारी डीजीपी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार' मामले में स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य में प्रभारी डीजीपी की परंपरा नहीं चलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

5 फरवरी 2026 को 'टी धंगोपल राव बनाम यूपीएससी' मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नियुक्ति में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट के शब्दों में, 'देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही सहित आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।' अगली सुनवाई से पहले छत्तीसगढ़ सरकार को या तो अरुण देव गौतम को पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करना होगा या आयोग को ऐसा ठोस कारण बताना होगा जो अदालत को संतुष्ट कर सके। ऐसा न होने पर मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी...जवानों ने 4आईईडी किया बरामद,4 नक्सली स्मारक भी ध्वस्त

रायपुर,15 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत का काउंट डाउन जारी है। जगंल क्षेत्र में जवानों की टीम लगातार अभियान चला रही है। कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में जवानों को सफलता हाथ लगी। हापाटोला-बीनागुंडा के जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के डंप में छिपाए गए कई आईईडी, नक्सली वर्दी और अन्य सामाग्री बरामद की गई है। वहीं कलपर-आमाटोला में नक्सलियों के 4 स्मारकों पर जवानों ने धवस्त किया है। जानकारी के मुताबिक, डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम 15 मार्च को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान ग्राम हापाटोला-बीनागुंडा के जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प से 3 प्रेशर कुकर आईईडी और 1 पाइप आईईडी बरामद किया गया। इसके अलावा बिजली वायर का बंडल,नक्सली वर्दी,फटाखा, नक्सल साहित्य सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। वहीं ग्राम कलपर और आमाटोला में बनाए गए 4 नक्सली स्मारकों को भी जवानों ने ध्वस्त कर दिया। सर्चिंग के दौरान डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने हापाटोला और बिनागुंडा के जंगल में नक्सली डंप बरामद किया। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाए आईईडी को बरामद किया।

बिना मान्यता एडमिशन के विज्ञापन पर हाईकोर्ट सख्त.... 5 स्कूलों को नोटिस जारी,शिक्षा सचिव से मांगा पर्सनल एफिडेविट,पुराने आदेशों पर भी मांगी रिपोर्ट

रायपुर,15 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के एडमिशन विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित स्कूल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर की गई।

शिकायतों पर कार्रवाई नहीं,कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने कोर्ट को बताया कि उनकी शिकायतों को 5 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने दुर्ग,रायपुर और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजकर एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन करते हुए अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

एडमिशन विज्ञापन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

इंटरवीनर ने अदालत के सामने एक पत्रिका में प्रकाशित एडमिशन विज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इसमें सत्र 2026-27 के लिए कई निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू होने की जानकारी दी गई थी। याचिका में कहा गया कि ये स्कूल आवश्यक मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं इसके बावजूद एडमिशन का विज्ञापन देकर छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसे अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया गया।

किड्स एकेडमी के पांच ब्रांच शामिल

एडमिशन विज्ञापन में जिन स्कूलों का उल्लेख किया गया। इनमें तुलसी कृष्णा किड्स एकेडमी, मोवा के अलावा कृष्णा किड्स एकेडमी के ही शंकर नगर,न्यू राजेंद्र नगर,सुंदर नगर और शैलेंद्र नगर ये चार ब्रांच शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में कृष्णा पब्लिक स्कूल,तुलसी (रायपुर) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

बीजापुर में पोटा केबिन हॉस्टल की 3 छात्राएं प्रेग्नेंट

दो 12वीं और एक 11वीं की छात्रा,इनमें 2 नाबालिग वार्डन बोलीं-घटना मेरे कार्यकाल की नहीं

बीजापुर,15 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की 3 आदिवासी छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। ये छात्राएं पोटा केबिन आवासीय संस्था (आरएमएसए) में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। इनमें से 2 छात्राएं कक्षा 12वीं और एक छात्रा कक्षा 11वीं की हैं। 2 छात्राएं नाबालिग हैं और सभी करीब पांच माह की गर्भवती हैं। छात्राओं के गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद उन्हें लगभग 5 माह पहले संस्था से हटा दिया गया था। इसके बाद से वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही थीं। हालांकि, कक्षा 12वीं की दो छात्राओं ने शनिवार को अपनी अंतिम परीक्षा दी है। हॉस्टल वार्डन का कहना है कि 'ये मेरे कार्यकाल का मामला नहीं' है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए : इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आवासीय

विद्यालय से आ रही ये खबर चिंता पैदा करती है। पता चला है कि अब सरकारी अमला इस मामले को रफा दफा करने में जुट गया है। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने घटना को लेकर सोशल मीडिया में लिखा प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आदिवासी असुरक्षित होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सुशासन का नारा देती है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल आश्रमों में पढ़ने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? इस मामले में जब पोटा केबिन आवासीय संस्था की अधीक्षिका से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह घटना उनके कार्यकाल का नहीं है और छात्राएं लंबे समय से संस्था से अनुपस्थित हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)